ज्ञानामृत

खुद के लिये जीनेवाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिये जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिये जीते हैं।

▶▶ श्री परमहंस योगानंद

राष्ट्र को समर्पित

विजय मत

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

www.vijaymat.com | शहडोल, बुधवार, 02 जुलाई 2025 | वर्ष- 08 | अंक- 188 | पेज- 08 | मूल्य- ₹5.00/-

न्यूज इन शॉर्ट

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पुरस्कार-2025 योजना की अधिसूचित

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025' की योजना को अधिसूचित किया। कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, इस योजना के लिए नामांकन और पंजीकरण हेतु एक वेब पोर्टल औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और उसके बाद नामांकन जमान किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह योजना भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देने के मकसद से तैयार की गई है। इसमें संतृप्ति आधारित दृष्टिकोण, आंकड़ों या दस्तावेजी प्रमाणों का संग्रहण, सुशासन और योजनाओं के रि यान्वयन में गुणात्मक पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। इस योजना का मूल्यांकन 11 प्राथमिकात वाले क्षेत्रों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के आधार पर किया जाएगा।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
Ministry Of Personnel, Public Grievances & Pensions

जून 2025 में जीएसटी कलेक्शन 6.2 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। मंगलावर को सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में सकल जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। घरेलू लेनदेन से सकल राजस्व 4.6 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात से जीएसटी राजस्व 11.4 प्रतिशत बढ़कर 45,690 करोड़ रुपये हो गया। जून महीने में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मंगलावर को सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह 1.84 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। एक साल पहले यह 1.73 लाख करोड़ रुपये था। पिछले महीने जीएसटी संग्रह 2.01 लाख करोड़ रुपये रहा। इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2.37 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया।

ईग्नू ने बढ़ाई जुलाई सत्र के लिए पुनः पंजीकरण करने की समय सीमा

नई दिल्ली, एजेंसी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2025 सत्र के लिए कार्यर् मों के लिए पुनः पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। जो छात्र पहले से ही इग्नू के किसी पाठ्यर् म में नामांकित हैं, उन्हें अपना पाठ्यर् म जारी रखने के लिए 15 जुलाई से पहले अगले सत्र के लिए खुद को फिर से पंजीकृत करना होगा। संबंधित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पुनः पंजीकरण कर सकते हैं। इग्नू पुनः पंजीकरण पोर्टल पर लिखा है कि छात्र फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। किसी भी प्रकार की देरी या भुगतान विफलता के कारण पुनः पंजीकरण असफल हो सकता है। इग्नू ने छात्रों को सलाह दी है कि वे कोई भी कोर्स चुनने से पहले उसके विवरण को ध्यान से पढ़ें।

आज जारी होंगे जोसा काउंसलिंग 2025 राउंड-3 के सीट आवंटन

नई दिल्ली, एजेंसी। संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण आज 2 जुलाई को जोसा 2025 राउंड 3 सीट आवंटन जारी करेगा। आवंटन जारी होने के बाद, उम्मीदवारों को 4 जुलाई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग (सीट की पुष्टि/शुल्क भुगतान/दस्तावेज़ अपलोड/उम्मीदवार द्वारा प्रश्नों का उत्तर) पूरी करनी होगी। आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और जीएफटीआई के लिए जोसा 2025 राउंड 1 और 2 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक भी जारी कर दी गई है। सभी राउंड के लिए जोसा कटऑफ चेक करने का लिंक इस पेज पर नीचे उपलब्ध है। जोसा काउंसलिंग 2025 का पूरा संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसे इस पेज पर नीचे देखा जा सकता है। इस साल, जोसा काउंसलिंग छह राउंड में पूरी होगी। काउंसलिंग के नियम वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

मोहन कैबिनेट: भोपाल में खुलेगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी, 1766 पुलों का पुनर्निर्माण

विजय मत, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में 'मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना' को स्वीकृति दी गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों को सतत विकास की मिसाल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है। साथ ही, क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने प्रेसवार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

4572 करोड़ की लागत से 1766 पुलों के पुनर्निर्माण को स्वीकृति
राज्य मद अंतर्गत क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक की योजना को 4572 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इससे राज्य में बारहमासी संपर्क सुविधा सुगम होगी। योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को अधिकृत किया गया है।

भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना... गाँधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के एक परिसर की स्थापना भोपाल में की जाएगी। इसके लिए तीन वर्षों तक प्रति वर्ष 1.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। 10 एकड़ भूमि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय को हस्तांतरित की जाएगी। अस्थायी तौर पर आरआरयू का संचालन आरजीपीवी के उपलब्ध भवन में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना

उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा से एक ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा, जिसकी जनसंख्या कम से कम 2000 हो तथा गौ-वंश की न्यूनतम संख्या 500 हो। इन्हें "मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम" के रूप में आत्मनिर्भर मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं, बल्कि ग्राम्य जीवन को आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन के साथ प्रगतिशील बनाना है।

योजना के अंतर्गत किए जाएंगे कार्य

- **गौ-पालन एवं डेयरी विकास:** ग्रामीणों को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा।
- **पर्यावरणीय नवाचार:** जैविक कृषि, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- **अधोसंरचना विकास:** गौशाला, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी, सोलर स्ट्रीट लाइट, सड़कों, नालियों और पुस्तकालयों का निर्माण।
- **रोजगार व आजीविका:** नंदन फलोद्यान, पोषण वाटिका, दुग्ध कलेक्शन सेंटर, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु वनोपज आधारित इकाइयाँ।
- **सामुदायिक समावेशन:** बायोगैस संयंत्र, शांतिधाम, गौ समाधि, सार्वजनिक उद्यान, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर।
- **डिजिटल व संस्थागत विकास:** ई-पंचायत, सीएससी सुविधा, समग्र ई-केवाईसी, पंचायत की आय के स्रोत।
- **स्वच्छता व पर्यटन:** ग्रे वॉटर मैनेजमेंट, मल-कीचड़ प्रबंधन, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होमस्टे सुविधा।

पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में मेस संचालन की स्वीकृति

प्रदेश के 108 विभागीय छात्रावासों में निवासरत 9050 विद्यार्थियों के लिए मेस संचालन को 31 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी गई है। इसमें 14 करोड़ अनावर्ती और 17 करोड़ आवर्ती व्यय सम्मिलित है। यह निर्णय विद्यार्थियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा।

न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 1266 नवीन पदों की स्वीकृति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176(3) के अंतर्गत अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने के दृष्टिगत 1266 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें 202 वैज्ञानिक अधिकारी शामिल होंगे। मध्यप्रदेश यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

नवगठित जिलों में जनजातीय व अजा कार्यालयों की स्थापना

मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में जिला संयोजक जनजातीय तथा अनुसूचित जाति कार्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 48 पद स्वीकृत किए गए हैं और 381.30 लाख रुपये का वार्षिक व्यय अनुमोदित किया गया है।

हेमंत खंडेलवाल होंगे मध्यप्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष, आज होगा ऐलान

विजय मत, भोपाल

बैतूल विधायक हेमंत विजय खंडेलवाल मध्यप्रदेश भाजपा के निर्विरोध नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हालांकि ऐलान बाकी है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने सीएम डॉ. मोहन यादव को इशारा किया और सीएम खंडेलवाल को मंच पर ले गए। सीएम डॉ. मोहन उनके प्रस्तावक बने। खंडेलवाल पहली पंक्ति में मंत्री वीरेंद्र खटीक और गोपाल भार्गव के बीच में बैठे थे। सीएम मोहन यादव इशारा मिलते ही उनको पीठ पर हाथ रखकर मंच की ओर बढ़े। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर और पर्यवेक्षक सरोज पांडे के सामने उन्होंने नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक समेत पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बुधवार सुबह 10:30 बजे भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होगी। माना जा रहा है इसी दौरान या इसके बाद खंडेलवाल के निर्विरोध निर्वाचन का औपचारिक ऐलान होगा।

प्रदेश भाजापाध्यक्ष वीडी शर्मा ने नामांकन के बाद मीडिया से कहा- मध्य प्रदेश भाजपा चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में बुधवार को भाजपा प्रदेश सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं ने संगठन पर्व 2024 में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

डिजिटल भारत के साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा-

अगला दशक होगा और भी परिवर्तनकारी

नई दिल्ली, एजेंसी

डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष पूरे हो चूके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जश्न मनाते हुए अपने आधिकारिक लिंक्डइन हैंडल पर डिजिटल इंडिया का एक दशक शीर्षक से एक ब्लॉग साझा किया है। उन्होंने डिजिटल इंडिया के दस वर्षों का सफर बयां किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार भारत 2014 में सीमित इंटरनेट पहुंच और डिजिटल सेवाओं से 2024 में डिजिटल प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले लोग इस बात पर संदेह करते थे कि भारतीय लोग तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन सरकार ने लोगों पर भरोसा किया और अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को भरने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया। आज, डिजिटल उपकरण 140 करोड़ भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। शिक्षा और व्यवसाय से लेकर सरकारी सेवाओं तक इसकी पहुंच है। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत में करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। अब यह संख्या 97 करोड़ से ज्यादा हो गई है। हाई-स्पीड इंटरनेट गलवान और सियाचिन जैसे दूरदराज के इलाकों में भी पहुंच गया है। देश का 5जी रोलआउट दुनिया में सबसे तेज है। इसमें सिर्फ दो साल में करीब 5 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

मुसीबत बना रेलवे का नियम: 25 प्रतिशत वेटिंग टिकट ने बढ़ाई मुश्किलें

ऑफ सीजन में भी ट्रेनें रिग्रेट, वेटिंग टिकट भी नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी

रेलवे द्वारा हाल ही में लागू किए गए एक नए नियम ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब गर्मी की छुट्टियों का सीजन खत्म हो चुका है और बड़े त्योहार भी दूर हैं, फिर भी उत्तर भारत की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रिग्रेट की स्थिति में चल रही हैं। यानी न केवल कंफर्म टिकट, बल्कि वेटिंग या आरएसी टिकट भी उपलब्ध नहीं है। रेलवे ने 16 जून 2025 से एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत किसी भी ट्रेन के किसी कोच में 25% से अधिक वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी कोच में 100 सीटें हैं, तो उसमें केवल 25 वेटिंग टिकट ही दिए जा सकते हैं। इससे अधिक की अनुमति नहीं है। इस नियम का सबसे ज्यादा असर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में देखा जा रहा है। मुंबई-जयपुर, अरावली एक्सप्रेस, बांद्रा-हिसार सुपरफास्ट, स्वराज एक्सप्रेस, गोवा संपर्क क्रांति जैसी कई ट्रेनें रिग्रेट की स्थिति में हैं। लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों की स्थिति भी यही है। 12229 लखनऊ मेल, 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस, 12565 बिहार सम्पर्क्रांति जैसी प्रमुख ट्रेनों में 5 जुलाई से 30 जुलाई तक सीटें उपलब्ध नहीं हैं। खासतौर पर थर्ड एसी इकॉनमी, थर्ड एसी और सेकंड एसी कोचों में सीट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। यात्रियों का कहना है कि यह नियम उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें आपात स्थिति में यात्रा करनी होती है। कई यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द तक करनी पड़ रही है। उनकी मांग है कि रेलवे को अस्थायी कोच जोड़ने, सीटों की संख्या बढ़ाने और नियम की समीक्षा जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह नियम प्रतीक्षा सूची नियंत्रित करने और बुकिंग प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

डिजिटल इंडिया पर बोले खरगे

दावे खोखले, हकीकत इससे काफी अलग

नई दिल्ली, एजेंसी

कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर डिजिटल इंडिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के दावे खोखले हैं और हकीकत इससे काफी अलग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए खरगे ने बताया कि भारतनेट परियोजना के तहत देश के 6.55 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक 4.53 लाख गांव यानी 65प्रतिशत गांव इससे वंचित हैं।

प्रति व्यक्ति ऋण बढ़कर 4.8 लाख रुपये हुआ, होम लोन और गैर-आवासीय उधारी में तेज इजाफा

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत में व्यक्तिगत उधराकर्ताओं का औसत ऋण बोझ बीते दो वर्षों में तेजी से बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में जहां प्रति व्यक्ति औसत ऋण 3.9 रुपये लाख था, वो मार्च 2025 तक बढ़कर 4.8 लाख रुपये पर पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति ऋण, सरकार के कुल ऋण का एक माप है, जो यह दर्शाता है कि प्रत्येक नागरिक पर कितना कर्ज बकाया है। ऋण स्तर में यह वृद्धि मुख्य रूप से उच्च रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के कारण हुई है। साथ ही, आवास ऋण में तेजी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल घरेलू ऋण का लगभग 29प्रतिशत हिस्सा गृह ऋण (होम लोन) से जुड़ा है। हालांकि, आवास ऋणों में वृद्धि समग्र रूप से स्थिर बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि नई लोन लेने वालों की तुलना में पुराने उधारकर्ता औसतन एक-तिहाई अधिक राशि का ऋण ले रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत का घरेलू ऋण लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र से उधारी में वृद्धि है।

रिपोर्ट में लोन-टू-वैल्यू (एलटीवी) अनुपात का बढ़ना वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय बन सकता है। 70 प्रतिशत से अधिक एलटीवी अनुपात वाले उधारकर्ता खातों की हिस्सदारी बढ़ रही है। इसके अलावा निम्न-रेटेड और अधिक ऋणग्रस्त उधारकर्ताओं के बीच जोखिम की स्थिति बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 75 साल के इतिहास में पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू की है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पदों पर नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नीति 23 जून 2025 को लागू हुई। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक कामकाज में बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि जजों पर आरक्षण लागू नहीं होगा और सिर्फ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट सहायक, चैंबर अटेंडेंट आदि पदों पर आरक्षण लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के तहत तीन कैटेगरी होंगी, जिनमें एससी, एसटी और गैर आरक्षित शामिल होंगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने कई योजनाओं को दी मंजूरी

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी, नई खेल नीति पर लगी मुहर

नई दिल्ली, एजेंसी

मोदी सरकार ने देश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ईएलआई) स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह योजना खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जो पहली बार रोजगार शुरू कर रहे हैं। वहीं, दूसरा हिस्सा लगातार रोजगार देने वाली कंपनियों को समर्थन देने के लिए होगा। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे के चार लेन बनाने के लिए 1,853 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। सरकार ने मंगलवार को रोजगार सृजन, कौशल बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

विजय मत एंकर — शिक्षा क्षेत्र के लिए गूगल ने अपने एआई टूल्स का बड़ा अपडेट जारी किया

गूगल ने शिक्षकों और छात्रों के लिए लॉन्च किए 30 नए एआई टूल्स

नई दिल्ली, एजेंसी

तकनीकी दिग्गज गूगल ने शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को एक नई दिशा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन (ISTE) सम्मेलन के दौरान गूगल ने 'Gemini in Classroom' नाम से एआई टूल्स की एक नई सीरीज लॉन्च की है। इस अपडेट के तहत शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए अनेक उन्नत फीचर्स और एप्लिकेशन पेश किए गए हैं।

गूगल ने स्पष्ट किया है कि इस एप में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता दी गई है। बच्चों की चैट या संवादों का इस्तेमाल एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा। इसके लिए गूगल ने चाइल्ड सेफ्टी एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर पॉलिसी तैयार की है।

शिक्षकों के लिए 30 से अधिक नए एआई टूल्स

गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है कि Google Workspace for Education उपयोगकर्ताओं के लिए ये सभी एआई टूल्स बिलकुल मुफ्त होंगे। पिछले साल गूगल क्लासरूम में Gemini फीचर को शामिल किया गया था, और अब उसकी क्षमताओं को और बढ़ाया गया है।

- एआई की मदद से पाठ योजनाएं तैयार कर सकेंगे।
- ऑटोमेटिक क्विज जनरेशन कर सकेंगे।
- प्रेजेंटेशन और वर्कशीट डिजाइन कर सकेंगे।
- छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आइडियाज तैयार कर सकेंगे।
- अध्ययन को गेमिफिकेशन के जरिए रोचक और इंटरएक्टिव बना सकेंगे।

छात्रों के लिए जैमिनी फॉर स्टूडेंट्स एप

गूगल ने छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार 'जैमिनी फॉर स्टूडेंट्स' एप भी लॉन्च किया है। इस एप के मुख्य फीचर्स में शामिल हैं...

- जैमिनी कैनवास जिसके जरिए छात्र किसी भी विषय पर पर्सनलाइज्ड क्विज तैयार कर सकेंगे।
- इंटरएक्टिव डायग्राम और विजुअल टूल्स, जिससे जटिल विषय भी आसानी से समझ सकें।
- अभिभावकों और शिक्षकों के लिए सुपरविजन और कंट्रोल टूल्स भी उपलब्ध होंगे।

जल्द आ रहे हैं NotebookLM और Gems फीचर्स

गूगल जल्द ही दो और प्रमुख एआई फीचर्स लॉन्च करने वाला है- NotebookLM की मदद से शिक्षक अपने कंटेंट से स्टडी गाइड और ऑडियो ओवरव्यू बना सकेंगे। Gems फीचर के जरिए शिक्षक एआई एक्सपर्ट असिस्टेंट्स तैयार कर सकेंगे, जो छात्रों को अतिरिक्त सपोर्ट प्रदान करेंगे।

कार्यालय: भोपाल ■ शहडोल ■ इंदौर ■ जबलपुर ■ होशंगाबाद ■ विदिशा ■ सीहोर ■ बैतूल ■ छिंदवाड़ा ■ ग्वालियर ■ ब्यौहारी ■ अनूपपुर ■ उमरिया ■ सीधी ■ सिंगरौली ■ रीवा ■ सतना ■ बालाघाट ■ सिवनी ■ कटनी ■ सागर ■ मुलताई ■ मुरैना ■ टीकमगढ़ ■ रायपुर ■ बिलासपुर ■ भिलाई

जिले में खरीफ सीजन की नई रणनीति, धान का रकबा घटाकर दलहन-तिलहन की खेती को बढ़ावा

धान पर निर्भरता में कमी, लाभकारी खेती की ओर कदम

विजय मत, शहडोल।

जिले में इस बार खरीफ सीजन की कृषि योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पारंपरिक धान की खेती की जगह अब दलहन एवं तिलहन की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार, इस परिवर्तन का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

पिछले वर्ष की तुलना में धान का रकबा कम

पिछले खरीफ सीजन में जिले में कुल 2 लाख 11 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती की गई थी, जिसमें से अकेले धान की खेती 1 लाख 46 हजार हेक्टेयर में की गई थी। लेकिन इस बार कुल खेती का लक्ष्य 2 लाख 18 हजार हेक्टेयर तय किया गया है, जिसमें धान की खेती घटाकर 1 लाख 42 हजार हेक्टेयर कर दी गई है। यह बदलाव इस सोच के साथ किया गया है कि किसान लाभदायक फसलों की ओर बढ़ें और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिले।

दलहन-तिलहन को मिला बढ़ावा

जिले में दलहन और तिलहन की खेती की संभावनाएं देखते हुए इन फसलों

का रकबा बढ़ाया गया है। पिछले सीजन में 21.26 हजार हेक्टेयर में तिलहन की खेती हुई थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 24 हजार हेक्टेयर कर दिया गया है। इसमें सोयाबीन का रकबा बढ़ाकर 13 हजार हेक्टेयर, तिल का रकबा 10 हजार हेक्टेयर और रामतिल की खेती 1 हजार हेक्टेयर में कराई जाएगी।

दलहनी फसलों में भी बढ़ोतरी

दलहनी फसलों की खेती भी इस बार विशेष रूप से बढ़ाई गई है। पिछले वर्ष 22.22 हजार हेक्टेयर में दलहन की खेती हुई थी, जिसे अब 27.50 हजार हेक्टेयर तक विस्तारित किया गया है। उड़द, मूंग, और अरहर की खेती को प्रमुखता दी जा रही है, जिसमें सबसे अधिक अरहर की खेती 14 हजार हेक्टेयर में होगी।

बोवनी की शुरुआत, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

जिले में खरीफ की फसलों की बोवनी शुरू हो चुकी है। अब तक लगभग 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी की जा चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, दलहन और तिलहन फसलें कम पानी में अधिक उत्पादन देती हैं और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं। इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ-साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित किए गए शिविर

शहडोल। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनजाति समुदायों के लिए समान अवसरों का सृजन, सामाजिक आर्थिक स्तर का विकास, शिक्षा स्वास्थ्य एवं आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति के उद्देश्य से जिले में 402 चिन्हित ग्रामों में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 जुलाई 2025 तक जिले मे तिथिवार शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ व सेवाओ की जानकारी दी जा रही है।

शहडोल जिले के ब्यौहारी जनपद पंचायत अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर आयोजित किये गए। शिविर में जन जातीय समुदायों को शासन के विभिन्न योजनाओं से अवगत कराते हुए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अधिक से अधिक इसका लाभ लेने हेतु अपील की गई। शिविर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजना एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी देने के साथ जनजातीय समुदाय के उपस्थितजनो से आवेदन पत्र भी प्राप्त किए गए।

शिविर में आधार कार्ड सुधार, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र,पीएम किसान, जन धन खाता, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, सहित अन्य सभी योजनाओं एवं सेवाओ की जानकारी दी गई। शिविर में संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच पंच जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

जनजातीय विद्यार्थियों का नेशनल स्कालरसिप पोर्टल (एनएसपी) पर वन टाईम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) होना अनिवार्य

शहडोल। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जानकारी दी है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कक्षा 9 वीं से महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जिन्हे केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक/पो.मै. छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय सीमा राशि रूपये 2. 50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है उन्हे वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कालरसिप पोर्टल (एनएसपी) पर वन टाईम. रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार ओटीआर नम्बर प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नम्बर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए पृथक से पुनः ओटीआर की आवश्यकता नही होगी।

कक्षा 9 वी से महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ओटीआर नम्बर प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणो मे सम्पन्न होगी (जिसकी प्रक्रिया संलग्न है) प्रथम चरण में विद्यार्थी को नेशनल स्कालरसिप पोर्टल के बेवसाईट से अथवा मोबाईल पर एनएसपी-ओटीआर मोबाइल एप डाउन लोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी जाकर रेफरेन्स नम्बर प्राप्त करना होगा, द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार फेस आरडी सर्विस एप डाउन लोड कर रेफरेन्स नम्बर के माध्यम से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नम्बर प्राप्त करना होगा। एमपी टॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन करते समय ओटीआर नम्बर दिया जाना अनिवार्य है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो डायलिसिस मशीन का हुआ शुभारंभ

नगर पालिका का यह प्रयास स्वास्थ्य सुविधाओं में और अधिक इजाफा करेगा जय- श्री मरावी

विजय मत, धनपुरी।

स्वास्थ्य सुविधाओं में और अधिक इजाफा हो नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसे लेकर प्रदेश की सरकार कृत संकल्पित है और आज अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसी का नतीजा है कि नागरिकों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है आज इस धनपुरी नगर के अंदर नगर पालिका परिषद के द्वारा जो दो नग डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराई गई है यह इस बात को बताती है कि विकास के कामों को लेकर हम जितना अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उतना ही तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में भी काम कर रहे हैं आज इस मशीन के यहां पर लग जाने से निश्चित है कि डायलिसिस के जो मरीज हैं उनकी सुविधा बढ़ेगी उक्त बातें जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयसिंह मरावी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस मशीन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर कहीं।

इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में जिला योजना समिति की सदस्य श्रीमती अमिता चपरा भाजपा मंडल धनपुरी के अध्यक्ष हेमंत सोनी नगर पालिका

उपाध्यक्ष हनुमान खंडेलवाल मंचासीन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रविंदर कौर छावड़ा ने की।

स्वास्थ्य सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी -जयसिंह मरावी

जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जय सिंह मरावी ने कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद धनपुरी की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से आज इस शासकीय अस्पताल में दो डायलिसिस मशीन लगवाई गई है निश्चित है कि इससे संबंधित मरीजों को इसका लाभ मिलेगा और अगर देखा जाए तो नगर पालिका का यह प्रयास निश्चित ही इस बात को बताता है कि नगर विकास के साथ-साथ नगर के महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान को लेकर भी वह निरंतर प्रयासरत रहती है।

नपा का यह प्रयास सराहनीय -अमित चपरा

कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि जिला योजना समिति की सदस्य श्रीमती अमिता चपरा ने कहा कि नगर पालिका धनपुरी के द्वारा इस चिकित्सालय में जो डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराई गई है यह प्रयास पूरी परिषद की सराहनी है निश्चित है कि जब हम बेहतर कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसे कार्य जो कि सीधा नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है उसमें यह प्रयास प्रशंसनी होती है आज इस चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन लग जाने से किडनी से संबंधित मरीजों को इसका लाभ मिलेगा इसके साथ-साथ इस चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी यहां पर और बेहतर सुविधाएं बढ़े इसे लेकर जो भी प्रयास होगा वह किया जाएगा।

प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत छूटे हुए विद्यार्थियों को पुनः अंतिम अवसर 7 नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का सुनहरा मौका

विजय मत, शहडोल।

1 जुलाई 2025 – पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) के कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय में स्नातक (बी.ए., बी.एससी.), स्नातकोत्तर (एम.ए., एम.एससी.) एवं विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में तृतीय चरण में प्रगति पर है।इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के करियर निर्माण को ध्यान में रखते हुए कुछ नवीन और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की गई है, जिनमें शामिल हैं– बी.एससी. फॉरेंसिक साइंस (न्यायिक विज्ञान) बी.एससी. लाइब्रेरी साइंस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन नवीन पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों से अत्यधिक सराहना एवं रुचि प्राप्त हो रही है।

प्रथम एवं द्वितीय चरण में जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया था तथा मेरिट सूची में चयनित हुए थे, किंतु समय पर प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर सके, ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय अंतिम अवसर प्रदान कर रहा है।

वे सभी विद्यार्थी दिनांक 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।यह अंतिम अवसर है, अतः सभी संबंधित विद्यार्थी समय रहते इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें।

शुरू हुई बरसात कोयला खदानों में बेहतर व्यवस्था को लेकर प्रबंधन कर रही बेहतर प्रयास

विजय मत, धनपुरी।

एसईसीएल सोहागपुर एरिया की कोयला खदानों में इन दोनों जहां उत्पादन लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के मौसम को देखते हुए प्रबंधन की ओर से कोयला खदानों में व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है ताकि बरसात के समय पर ओपन कास्ट खदानों में कोयला उत्पादन सहित कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कतो का सामना न करना पड़े बरसात के समय पर ओपन कास्ट खदानों में जल भराव की स्थिति सबसे अधिक देखने को मिलती है और इसे देखते हुए प्रबंधन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है ताकि खदानों में पानी भरने की स्थिति में कोयला उत्पादन पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े वहीं दूसरी तरफ ओपन कास्ट खदानों में सड़कों की स्थिति को सुधारने की दिशा में भी ध्यान दिया जाएगा। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मेगा प्रोजेक्ट रामपुर ओपन कास्ट एवं अमलाई ओपन कास्ट जहां पर सबसे अधिक कोयला उत्पादन हो रहा है और हर वर्ष देखा जाता है की बरसात के समय पर भी यहां की बेहतर व्यवस्था के कारण उत्पादन निरंतर चलता रहता है क्योंकि प्रबंधन बरसात से पहले ही इन दोनों ओपन कास्ट में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में काम करना शुरू कर देती है और बरसात शुरू होते ही यहां की व्यवस्थाएं साफ तौर पर देखने को मिलती है एरिया महाप्रबंधक लगातार कोयला खदानों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर कोयला उत्पादन से संबंधित जहां जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बरसात को देखते हुए यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर क्या किया जा रहा है इस पर भी चर्चा कर रहे है महाप्रबंधक ने कहा है की बरसात को देखते हुए ओपन कास्ट खदानों में व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए सभी प्रयास किया जाए इतना ही नहीं खदानों के अंदर जो सड़के हैं ।

जल गंगा संवर्धन अभियान का विधायक की उपस्थिति में किया गया समापन

जल गंगा संवर्धन अभियान अन्तर्गत करकी ग्राम में कुल 08 खेत तालाब एवं 04 डगबेल रिर्चाज का कार्य किया गया

विजय मत, शहडोल।

जनपद पंचायत जयसिहनगर अन्तर्गत ग्राम पंचायत करकी मे विधायक विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी शरद जुगलाल कोल की उपस्थिति में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन किया गया। ग्राम पंचायत करकी में जल गंगा संवर्धन अभियान अन्तर्गत कुल 08 खेत तालाब एवं 04 डगबेल रिर्चाज का कार्य किया जा रहा है।

जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत स्वीकृत जल संरचनाएं जब पूर्ण होगी तो भू जल स्तर में वृद्धि होगी तथा जिन किसानो के खेत में खेत तालाब बनाए गए है उन किसानो को खेत की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। जिससे ये किसान उद्यानिकी, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां भी संचालित कर सकेंगे। ये विचार ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शरद जुगलाल कोल ने ग्राम करकी में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम को सम्बोंधित करते हुए व्यक्त किए।

सीईओ जनपद पंचायत ने बताया कि जनपद पंचायत जयसिंहनगर में 870 खेत तालाब 130 डगवेल रिचार्ज तथा 5 अमृत सरोवर तालाब स्वीकृत कर जल संरक्षण और संवर्धन का कार्य जन आंदोलन के रूप में किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर नवीन खेत तालाब के हितग्राहियों एवं जल दूतो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्रीमती शिवानी जैन, एपीओ श्री मनोज मिश्रा, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, नवीन खेत तालाब के लाभान्वित हितग्राही, जलदूत सहित ग्रामवासी उपस्थित रहें

रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की थैंक्स गिविंग कार्यक्रम के साथ क्लब के सत्र 2024-25 का हुआ समापन

विजय मत, शहडोल।

रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3261 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटे अखिल मिश्र के निदेशानुसार रोटरी क्लब जबलपुर से ऑफिसियल विजिट पर पधारे असिस्टेंट गवर्नर रोटे ष्ट राकेश खंडेलवाल एवं पूर्व अध्यक्ष रोटे राजेश साहू ने रोटरी क्लब शहडोल के साथ हुई बैठक में क्लब के द्वारा वर्ष भर किये गए कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की।

क्लब के वर्तमान अध्यक्ष रोटे संजय शर्मा ने विस्तृत रूप से शहर में किये गए क्लब की सभी गतिविधियों एवं उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया एवं रोटरी क्लब शहडोल द्वारा जिला अस्पताल में स्थापित निशुल्क प्याऊ तथा रजिस्ट्रेशन के लिये आने वाले वृद्ध वा असहाय मरीजों हेतु बेंच प्रतिस्थापन का अवलोकन कराया गया,जिसकी उन्होंने अत्यंत सराहना की जिससे अधिकारीगण अत्यंत प्रभावित हुए एवं इसकी प्रशंसा की एवं आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

इसके उपरांत अध्यक्ष संजय शर्मा के द्वारा होटल ग्रीन गार्डन में एक अनौपचारिक थैंक्स गिविंग कार्यक्रम रखा गया जिसमें क्लब के सभी रोटेरियन सदस्य अपने परिवार सहित उपस्थित रहे। क्लब के अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव सत्येंद्र सोनी एवं कोषाध्यक्ष डॉ दीपक कुशवाहा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों वर्ष भर अपना विशेष सहयोग एवं योगदान देने वाले सदस्यों एवं मीडिया से जुड़े मित्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।प्रमुख रूप से सम्मानित होने वाले सदस्यों में रोटे विजय दुबे अजय बिजरा प्रकाश गुप्ता राजेश श्रीवास्तव मनीष केजरीवाल एस राजेश गुप्ता डॉ अनिल उपाध्याय डॉ आर डी दुबे डॉ अभिषेक गर्ग डॉ निकिता सोनी अमित गुप्ता बंटी मोनिका दुबे विनोद प्रधान डॉ अपर्णा उपाध्याय सतेंद्र सोनी डॉ दीपक कुशवाहा आदि शामिल रहे । साथ कि अध्यक्ष संजय शर्मा ने पूरे कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया एवं धन्यवाद ज्ञापित किया तथा आगामी अध्यक्ष रोटे के के गुप्ता एवं उनकी टीम को आगामी सत्र के लिये शुभकामनाएं दी उसके पश्चात सभी ने मनोरंजक गेम एवं एक शानदार डिनर का आनंद लिया एवं कार्यक्रम का समापन हुआ।

इस अवसर पर रोटे विनय तिवारी संजय कटारे डॉ उमेश नामदेव रविशंकर पाठक धर्मेंद्र नामदेव सतीश सराफ अजय मौर्य अनिल मोर राजेश गुप्ता अविनाश कस्तवार ऋतुराज गुप्ता अमित गुप्ता राहुल सिंघाई सुशील ताम्रकार राजेश पाठक सुनील पांडेय मृगेंद्र द्विवेदी संजय तिवारी नीलेश गुप्ता गोपाल शर्मा अजय मुँदरा संजीव श्रीवास्तव एस के पांडे राजेश कटारे देवेंद्र कुंदनानी श्रीमती अर्चना शर्मा ममता गुप्ता पूजा कुशवाहा डॉ सुधा नामदेव डॉ प्रीति गर्ग रीनू कटारे मंजू गुप्ता अनुपमा गुप्ता ऋचा केजरीवाल श्वेतांजलि पाठक रिंकी दुबे मेघा गुप्ता विनीता नामदेव वंदिता गुप्ता पूजा कस्तवार रीना सिंघाई नीलिमा पाठक श्रीमती ताम्रकार रितु मूंदड़ा सरिता मोर आदि उपस्थित रहे ।

Government of Madhya Pradesh
Urban Development & Environment Department
Office of the Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad SHAHDOL
Distt. SHAHDOL (M.P.)

N.I.T. /2757/ NPshahdol/e-tendering/ Date: 27.06.2025

Notice Inviting e-Tenders First Call

Online PERCENTAGE RATE bids for the following works are invited from registered contractors and firms of repute fulfilling registration criteria:

S.No./Pkg./Code	Name of Work	District	Portable Amount (Rs. In Rupies)	EMD (in Rupees)	Cost of Docume nt (in Rupees)	Categor y of Contract or	Period of Complet ion (in Month)
2025_UAD_433753-1	LT Extention Street lighting work ward no. 03 in municipal council SHAHDOL	SHAHDOL	875546/-	8755/-	2000/-	ELECTRICAL CONTRACTOR REGISTARTION IN ANY CLASS	01 Month

1. Interested bidders can view the detailed NIT & Other document on website https://mptenders.gov.in/nicgep/app (Department Name: "Urban Development Department").
2. The Bid Document can be purchased only online from (date) 28.06.2025 (time) 10.30AM TO 12.07.2025, 17:30 PM
3. Amendments to NIT, if any, would be published on website only, and newspaper.

Chief Municipal Officer
Nagar Parishad Shahdol District-Shahdol (M.P.)

न्यूज इन शॉर्ट

संगीतमय राष्ट्रगान के साथ की गई शासकीय काम काज की शुरूआत

उमरिया। संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की उपस्थिति में संगीतमय राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तथा मध्यप्रदेश के गान के साथ शासकीय काम काज की शुरूआत की गई। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत तथा मध्यप्रदेश गान के गायन की संगीतमय प्रस्तुति सोहन चौधरी एवं उनके दल व्दारा दी गई।

पुलिस अधीक्षक ने किया पांच हजार रूपये का ईनाम घोषित

उमरिया। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने थाना चंदिया जिला उमरिया के अपराध क्रमांक 183/25 धारा 137(2) बी एन एस के तहत अपहृता की दस्तयाबी, गिरफ्तारी संभव हो सके, के लिए घोषणा की है कि जो कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देगा जिससे आधार पर दस्तयाबी गिरफ्तारी संभव हो सके, को पांच हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। ईनाम वितरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक का अंतिम निर्णय होगा।

हाइवे पर मौजूद गड्ढ़े से गई मजदूर की जान

उमरिया। चंदिया थाना अंतर्गत दर्दनाक सड़क हादसे में पथरहठा निवासी संजय पिता भाईलाल सोनी उम्र 36 वर्ष की मौके पर मौत हो जाने का समाचार प्रकाश में आया है। जानकारी अनुसार सोमवार की रात करीब 8 बजे संजय एफसीआई गोदाम बिसहनी में ड्यूटी के बाद अपनी बाइक क्रमांक एमपी 54 एमए 5311 से घर लौट रहा था।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चंदिया हाइवे पर सड़क मरम्मत के लिए किया गया गड्ढा हादसे की वजह बना। बाइक सवार संजय जैसे ही उस स्थान पर पहुँचा, बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।जानकारी के अनुसार संजय एफसीआई गोदाम में कलेक्टर रेट पर मजदूरी करता था और रोज की तरह घर लौट रहा था। जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो गए। पड़ोसियों की मदद से उसकी तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंततः रात करीब 2 बजे चंदिया पुलिस द्वारा परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई।स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए हाइवे में की गई लापरवाह खुदाई और बिना संकेतक छोड़े सड़क मरम्मत कार्य को जिम्मेदार ठहराया है।अब परिजनों के साथ पूरे गांव में गम और आक्रोश का माहौल है।

खड्डी कॉलेज:राजधानी से समाप्त हुई अतिथि विद्वान की सेवा, एडी और लीड कॉलेज प्राचार्य के बीच फंसी रही जांच

सीधी। शासकीय महाविद्यालयों में सार्थक ऐप में फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान लेने वाले एक अतिथि विद्वान को बाहर का रास्ता उच्च शिक्षा विभाग ने दिखाया है, इसकी शिकायत हुई तो क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय में हुई थी लेकिन जांच प्रभारी एडी डॉ. आरपी सिंह और लीड कॉलेज सीधी प्राचार्य के बीच ही अटकी रही। इसी बीच शिकायत कर्ता ने शिकायत उच्च शिक्षा आयुक्त से की तो राजधानी स्तर पर जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। शासकीय कॉलेज में पदस्थ अतिथि विद्वान अभिनंदन पांडेय द्वारा गलत तरीके से हाजिरी लगाई जा रही थी। उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आरके गोस्वामी द्वारा जारी किए गए हैं। बता दें कि शासकीय कॉलेज खड्डी में मनमानी के संबंध में पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव रामप्रकाश तिवारी डैडू ने शिकायत प्रभारी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ. आरपी सिंह से की गई थी, उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया और लीड कॉलेज प्राचार्य सीधी को जांच सौंपने की बात कही लेकिन लीड कॉलेज प्राचार्य सीधी ने किसी प्रकार की जांच दिए जाने से इंकार कर दिया। इसके बाद पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव ने शिकायत उच्च शिक्षा आयुक्त से की थी। जिसके बाद मामले की जांच गंभीरता से कराई गई और शासकीय कॉलेज खड्डी में पदस्थ अतिथि विद्वान अभिनंदन पाण्डेय की हाजिरी गलत पाई गई। बता दें कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव ने शिकायत में शासकीय कॉलेज खड्डी में पदस्थ तीन अन्य अतिथि विद्वान डॉ. अजय सिंह गहरवार, डॉ. श्रीकांत द्विवेदी व प्रिंस मिश्रा द्वारा फर्जी तरीके से हाजरी लगाए जाने की शिकायत की थी। बताया गया उनके सार्थक ऐप के हाजिरी के संबंध में जांच की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग की इस कार्यवाही से जिले भर के शासकीय महाविद्यालयों में हडक़ंप मच गया है। शासकीय कॉलेज मड़वास में भी कुछ लोगो द्वारा गलत हाजिरी सार्थक एप में लगाए जाने की शिकातत है, इसकी भी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में अतिथि विद्वान न जाने के बाद भी हाजिरी लगा रहे थे, ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रभारी प्राचार्य डॉ. रामसुरेश भारती को नहीं थी लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्शन ऐसे मनमानी करने वाले अतिथि विद्वानों के खिलाफ नहीं लिया गया।

युवा टीम ने नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों को शॉल व तुलसी का पौधा भेंट कर ज्ञापित किया धन्यवाद

डॉक्टर्स डे पर चिकित्सालय सभागार में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन

विजय मत, उमरिया

डॉक्टर्स ने वैश्विक समस्या कोरोना महामारी से लड़ने में सबसे अधिक मदद की है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (नेशनल डॉक्टर्स डे) के अवसर पर जिले की सक्रिय युवाओं की टोली युवा टीम उमरिया के द्वारा डॉक्टर्स डे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय उमरिया में चिकित्सालय सभागार में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन कर उपस्थित समस्त डॉक्टर्स को शॉल व तुलसी पौधा भेंट किया।यह एक अनूठी पहल थी, जिसमें युवाओं ने डॉक्टरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए तुलसी का पौधा उपहार में दिया। तुलसी का पौधा, जिसे पवित्र माना जाता है, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, और यह भेंट डॉक्टरों के प्रति युवाओं की .तज्ञता और सम्मान का प्रतीक थी। कार्यक्रम का कुशल संचालन लैब टेक्नीशियन वीरेंद्र शर्मा के द्वारा किया गया।

सिविल सर्जन डॉ.के सी सोनी ने न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि समाज को डॉक्टरों की भूमिका और उनके मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देने की अपील की। उन्होंने ने थीम मुखौटे के पीछेरू उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है? पर विशेष ध्यान दिलाया। सभी विशेषज्ञों ने इस वर्ष की थीम की सराहना करते हुए कहा कि यह विषय समाज को यह याद दिलाने का अवसर है कि डॉक्टर भी इंसान हैं, और उन्हें भी सहानुभूति, समर्थन और समझ की ज़रूरत है।

टीम संयोजक हिमांशु तिवारी ने कहा कि डॉक्टर्स देश का एक अहम हिस्सा माना जाता है,कोरोना महामारी से उभरने में डॉक्टर्स ने एक अहम भूमिका अदा की है। देशभर में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कोविड-19 के खिलाफलड़ाई में भारत को अपने सभी चिकित्सकों पर गर्व है। देशभर में कोरोना महामारी के आने के बाद चिकित्सको की भूमिका सामने आई है। कोरोना की दो घातक लहरों के सामने के बाद भी देश के डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी और कोरोना जैसी बीमारी से निपटने में मदद की है। उन्होंने कहा कि धरती पर ईश्वर की अवधारणा के रूप में के रूप में डॉक्टर हैं। वैश्विक कोरोना महामारी के संकटकाल में सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने अद्भुत क्षमता के साथ सेवा प्रदान की है। डॉक्टरों ने अपने सम्मान के लिए युवा टीम के सदस्यों का आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल डॉक्टरों को सम्मानित करना था, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूकता फैलाना था।इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ के.सी सोनी, आरएमओ डॉ संदीप सिंह,डॉ बृजेश कुमार प्रजापति, डॉ एस के निपाने, डॉ सी.पी साक्या, डॉ सरफराज खान, डॉ मुकुल तिवारी, डॉ अनामिका तिवारी, डॉ राजीव रोचन द्विवेदी, डॉ एल.एन रूहेला,डॉ आर के प्रजापति, भूपेंद्र माझी, लैब टेक्नीशियन वीरेंद्र शर्मा,वर्षा विश्वकर्मा,युवा टीम से हिमांशु तिवारी, शिखा बर्मन,श्रीराम तिवारी,एवं सभी उपस्थित रहे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न

विजय मत, उमरिया

कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उमरिया अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनिज राजस्व प्राप्ति, वित्तीय वर्ष 2025-26 में दर्ज अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर की गई कार्यवाही, आर आर सी की वसूली के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर श्री जैन ने आरआरसी की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उप संचालक खनिज फरहद जहां ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 -26 में माह अप्रैल 2025 से जून 2025 तक का लक्ष्य 16.75 करोड़ के विरूध्द 9.87 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। इसी तरह अवैध उत्खनन के 12 प्रकरणों में 8 प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें 1.43 लाख रूपये की राजस्व प्राप्त हुई है। अवैध परिवहन के 17 प्रकरणों में से 12 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 5.50 लाख रूपये की राजस्व आय प्राप्त हुई। अवैध भंडारण के 1 प्रकरण में 0.39 लाख रूपये की राजस्व प्राप्त हुआ है।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, एसडीएम मानपुर टी आर नाग, एसडीएम पाली अंबिकेश प्रताप सिंह, एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले, हरनीत कौर कलसी सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को

उमरिया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायिक प्रकरण आपराधिक, सिविल, श्रम, मोटरयान दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, कुटुंब न्यायालय में लंबित, प्रिलिटिगेशन के समझौता योग्य प्रिलिटिगेशन के रूप में सभी बैंकों के प्रकरण, नगर पालिका समकेतिक कर एवं जलकर एवं विद्युत प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया ने अधिवक्ताओ एवं जन मानस से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों को आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निरा.त कराएं तथा आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं।

बाइक सवार को बचाने अनियंत्रित हुई बस सड़क से उतरी

विजय मत, उमरिया

मुख्यालय से सटे कारीमाटी के पास उमरिया से शहपुरा जा रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में उतर गई। इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक अन्य बस की मदद से अपनी यात्रा पुनः शुरू की। बस चालक ने बताया कि सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया था, जिसे बचाने के प्रयास में वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया।स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दे दी गई है। गनीमत रही कि मोड़ होने की वजह से बस की रतार धीमी थी,अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आम जनों की समस्याएं

विजय मत, उमरिया

साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने जिले के दूर दराज से आए आम जनों की समस्याओं को सुना तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग की ओर आवेदन प्रेषित किया।

जनसुनवाई में रेखा बारी शारदा कालोनी ने फौती नामांतरण कराने, शंकुतला बाई चंदिया ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने, वेवा बेटी बाई ग्राम बल्हौड़ ने अधिकार पत्र की जमीन को छीनने, मारपीट करने, लोटन गड़ारी ग्राम भरौला ने खेत तक जाने के लिए रास्ता दिलाने, शिवमंगली ग्राम महुरी ने प्राथमिक शाला महुरी में रसोईया का काम दिलाने, कौशल चौधरी चंदिया वार्ड क्रमांक 3 ने आग लगने से हुए नुकसानी की सहायता राशि दिलाने, अंजू निवासी मउहार ने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने, अजय सेन ग्राम चंदवार ने पिता की मृत्यु पश्चात संबल योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन किया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, डिप्टी कलेक्टर हरनीत कौर कलसी सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

अभिनव पाण्डेय का पहले ही प्रयास में एनडीए में चयन, वायुसेना में शामिल होकर करेंगे देश सेवा

विजय मत, उमरिया

अनुशासन वा कड़े परिश्रम और सही मार्गदर्शन से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है वायुसेना में अफसर बनकर देश की सेवा करने का सपना उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा मुख्यालय के रहने वाले अभिनव पाण्डेय ने संघ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित एनडीए की परीक्षा पास करके साकार किया है। मानपुर निवासी अभिनव पाण्डेय के एनडीए में चयनित होने पर शहरवासियों में उत्साह का माहौल है। अभिनव शहडोल सम्भागीय मुख्यालय के कोतवाली थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामराज पाण्डेय और सीएम राइज स्कूल में हिंदी की व्याख्याता स्मिता पाण्डेय के सुपुत्र हैं। अभिनव ने अपनी उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्ष 1 सितम्बर को आयोजित एनडीए की परीक्षा में उनका चयन वायु सेना में लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। अभिनव की प्रारंभिक शिक्षा पाली स्थित सेंट जोसेफइंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है उन्होंने अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के कोटा स्थित अकलंक पब्लिक स्कूल से हासिल की है। मिली जानकारी अनुसार अभिनव के दादा श्री छत्रपाल पाण्डेय पुलिस विभाग में निवर्तमान सहायक उपनिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं दादी श्री मती सुशीला पाण्डेय ने भी अभिनव की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है दादा छत्रपाल पाण्डेय ने खुशी साझा करते हुए कहा कि हमारे परिवार से कई लोगों ने भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल होकर देश की सीमाओं की रक्षा की है। लेकिन ये पहली बार है जब हमारे परिवार से हमारे नाती का चयन वायुसेना में सीधे अफसर के पद पर हुआ है। अभिनव का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी,खडकवासला के लिए हुआ है वहां वे तीन साल के कड़े प्रशिक्षण के बाद फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग हेतु इंडियन एयर फोर्स अकादमी हैदराबाद जाएंगे,उसके बाद भारतीय वायुसेना में बतौर लाईंग ऑफिसर अपनी सेवाएं देंगे।

गड़बड़ी

5 रुपए से लेकर 13 रुपए प्रतिदिन तक का भुगतान, मामला जिले के कुसमी जनपद पंचायत क्षेत्र का

मनरेगा में ये कैसा मजदूरी भुगतान, जनता हैरान

विजय मत, सीधी

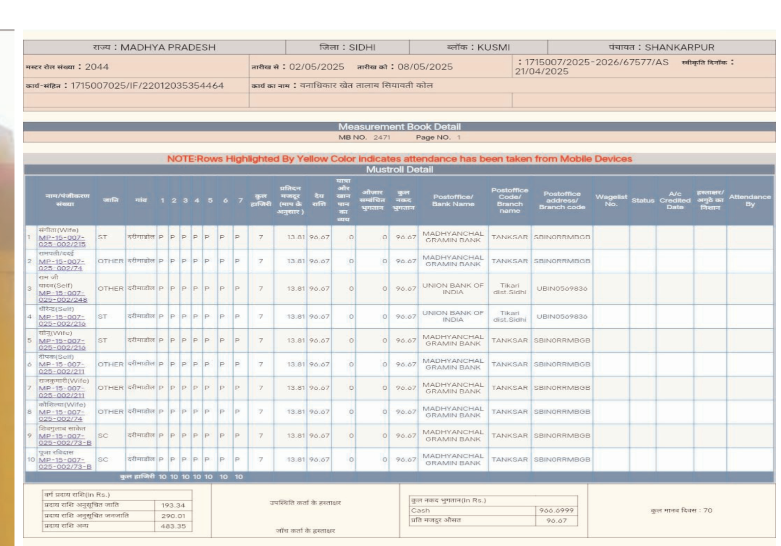

जिले के कुसमी जनपद पंचायत अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत मजदूरी भुगतान में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूरों को 261 रुपए प्रतिदिन की निर्धारित दर के बदले कहीं 5 रुपए तो कहीं 13 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया है।

उल्लेखनीय हैं लेकिन कुसमी जनपद की ग्राम पंचायत कतरबार में जितेंद्र कुशवाहा की भूमि पर बने खेत तालाब कार्य में मास्टर रोल क्रमांक 16552 में मजदूरी ?563 पैसे प्रतिदिन दर्शाई गई है। वहीं ग्राम पंचायत शंकरपुर में वन अधिकार के तहत बनाए गए खेत तालाब में मास्टर रोल क्रमांक 2044 पर मजदूरी ?13.81 प्रतिदिन दर्ज है। यह हाल सिर्फ दो ग्राम पंचायतों का नहीं बल्कि कुसमी क्षेत्र की कई पंचायतों में मजदूरों की मेहनत के साथ इसी तरह का खिलवाड़ किया गया है।

जनपद सीईओ का गैरजिम्मेदाराना बयान

जब इस गड़बड़ी को लेकर जनपद सीईओ ज्ञानेंद्र मिश्रा से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने इस पर अनभिज्ञता जताई और रटे-रटाए अंदाज़ में जांच कराएंगे का जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया।

जबकि कुसमी जनपद में पहले भी ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं। कुछ में कागज़ी कार्यवाही हुई, लेकिन सुधार की कोई स्थायी पहल अब तक नहीं की गई।

मजदूरों की मेहनत का उड़ाया जा रहा मज़ाक

261 रुपए प्रतिदिन की दर पर मजदूरी देने का प्रावधान है, लेकिन पोर्टल पर दर्ज आंकड़े खुद इस लूट की पोल खोलते हैं। मजदूरों को 5 से 13 रुपए प्रतिदिन देना न सिर्फ मनरेगा की आत्मा के साथ धोखा है, बल्कि गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा अमानवीय व्यवहार है।

16 जुलाई को चक्काजाम आंदोलन की चेतावनी

इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता आनंद सिंह ददुआ ने प्रशासन को चेताया है कि जनपद कुसमी अंतर्गत सभी पंचायतों मे ऐसे सभी भुगतान में अगर जल्द जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई,एवं मजदूरी भुगतान लंबित पाया गया तो वे 16 जुलाई को चक्का-जाम आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मजदूरी का मामला नहीं, यह आम जनता के साथ योजनाबद्ध ठगी है, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

संस्थापक
श्री रामसिपाही शुक्ल

ईरान ने स्वयंभू विश्व विजेताओं को दिखाया आईना

मध्य एशिया में मंडरा रहे युद्ध के बादल फ़िलहाल छंटते हुये नज़र आ रहे हैं। 13 जून को इस्त्राईल ने ईरान पर अचानक बड़ा हमला कर दिया था। इन हमलों में ईरान के उच्चस्तरीय 20 कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां कीं। दोनों ओर से ड्रोन व मिसाइल की बौछार 12 दिनों तक होती रही। इस्त्राईल के इतिहास में यह पहला मौक़ा था जब ईरान जैसे किसी देश ने धोखे से किये गये उसके हमलों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसकी इस्त्राईल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या इस्त्राईल की जनता ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। इस्त्राईल बनाम ईरान संघर्ष में इस्त्राईल के वजूद से सम्बंधित कुछ बातें कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकतीं। जर्मन तानाशाह एडोल्फ़ हिटलर के उत्पीड़न के बाद यहूदी मुख्य रूप से 1930 के दशक से 1940 के दशक के बीच फ़िलिस्तीनियों की अनुकम्पा से यहाँ बसने लगे। इस दौरान, लगभग 2,50,000 यहूदी फ़िलिस्तीन पहुंचे थे । द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बाद, विशेष रूप से होलोकॉस्ट के बाद, 1945 से 1948 तक यहूदी प्रवास फिर से बढ़ा, और 1948 में इस्त्राईल की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया और भी तेज़ हो गयी। चूँकि इस्त्राईल को अरब के इस क्षेत्र में बसाने में पश्चिमी देशों ख़ासकर अमेरिका व ब्रिटेन की दूरगामी सोच काम कर रही थी इसलिये इन देशों ने इसे भरपूर समर्थन देकर न केवल इनके फलने फूलने में इस्त्राईल की पूरी मदद की बल्कि क़ब्ज़े की इस ज़मीन पर अपने विस्तार के लिये की जाने वाली हिंसक कार्रवाइयों में भी हमेशा इनके साथ रहे। इसी अमेरिकी समर्थन का नतीजा है कि इस्त्राईल गत दो वर्षों में ग़ज़ा के लगभग 80 हज़ार बेगुनाह व निहत्थे लोगों को मार चुका है।और उसकी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अभी भी जारी है। दूसरी तरफ़ वह ईरान है जो पश्चिमी देशों की बांटो और राज करो की नीति का शिकार होकर ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 सदस्य देश होने के बावजूद पश्चिमी साज़िश के तहत केवल शिया-सुन्नी मतभेद के नाम पर हमेशा अलग थलग किया जाता रहा।

नोट

सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख-आलेख एवं विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं अतः यह जरूरी नहीं है कि विजय मत समूह उपरोक्त लेख या विचारों से सहमत हो। किसी लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार हैं।

मध्यप्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जल संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम

हर्षवर्धन पान्डे

मध्यप्रदेश सरकार ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की जो जल संरक्षण और संवर्धन के लिए एक जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान मध्यप्रदेश में जल संरक्षण के संकल्प के लिये जन-सहभागिता जुटाने में मील का पत्थर साबित हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस अभियान को एक व्यापक और समयबद्ध मिशन के रूप में शुरू किया। 30 मार्च 2025 को उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल देवता वरुण के पूजन और जलाभिषेक के साथ इसकी शुरुआत की। यह अभियान 30 जून 2025 तक चला, जिसमें 90 दिनों की अवधि में जल संरक्षण के लिए युद्धस्तर पर कार्य किए गए। इसके अतिरिक्त विश्व पर्यावरण दिवस से गंगा दशहरा तक विशेष रूप से जल स्त्रोतों की सफाई और पुनर्जनन पर ध्यान केंद्रित किया गया। पुरानी बावड़ियों, कुओं और तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनका दस्तावेजीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया।नदियों, तालाबों और कुओं की सफाई के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। विशेष रूप से, खंडवा जिले में नर्मदा की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ का सफल पुनरुद्धार किया गया।नर्मदा नदी से लगे शहरी क्षेत्र में घाटों की मरम्मत और सफाई कार्य को प्राथमिकता दी गई। नगरीय निकायों में 3300 से अधिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवन दिया गया। नगरीय क्षेत्र के 2200 नालों की सफाई और पुर्नसंचालन की क्षमता विकसित की गई। प्रदेश में 4 हजार वर्षा जल संचयन संरचनाएं तैयार की गई। प्रदेश के प्रमुख नगरों में 32 अमृत जल संरचनाएं एवं 38 हरित क्षेत्र कार्य पूर्ण किये गये। नगरीय निकायों के कर्मियों ने शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता का परीक्षण फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मानकों पर किया गया। मार्च 2025 से शुरू हुए अभियान में गर्मी के मौसम को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में 2700 सार्वजनिक प्याऊ और जल केन्द्रों की व्यवस्था की गई।

> जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जो प्रदेश में 31,800 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण किया गया, जिसमें बालाघाट जिला 561 तालाबों के साथ शीर्ष पर रहा। ये तालाब वर्षा जल संचयन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं।932 अमृत सरोवरों का संरक्षण और संवर्धन किया गया, और सरकार का लक्ष्य 1,000 सरोवरों को पूरा करना है। सिवनी जिले में इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। भूजल स्तर बढ़ाने के लिए तालाबों और कुओं का गहरीकरण, नाला विस्तारीकरण, चेकडैम निर्माण और सोकपिट रेट्रोफिटिंग जैसे कार्य किए गए।

स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के तहत जल संरचनाओं में मिलने वाले गंदे पानी के नालों को डायवर्जन के बाद शोधित करने की योजना लागू की गई। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार, 450 मिलियन लीटर घरेलू अपशिष्ट जल नदियों में प्रवाहित होता है। इसे रोकने के लिए 869 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी नवीनतम राज्य स्तरीय प्रदर्शन डैशबोर्ड के आकलन के अनुसार खंडवा मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। इससे पूर्व केन्द्रीय एजेंसी ने जल संरक्षण कार्यों के लिए खंडवा को देश का शीर्ष जिला घोषित किया है। इस सूची में मध्यप्रदेश को चौथा स्थान मिला है।

खेत-तालाब निर्माण का लक्ष्य 77,940 तय किया गया था लेकिन प्रदेश में 79,815 खेत-तालाबों का निर्माण हो रहा है, जो शत प्रतिशत से भी अधिक है। अभियान की अवधि में प्रतिदिन औसतन 1,078 खेत-तालाबों के निर्माण का प्रारंभ किया जा रहा है। डगवेल रिचार्ज संरचनाओं के लिये 1,03,900 के लक्ष्य में से 1,00,321 संरचनाओं का निर्माण जारी है जो लक्ष्य का 96.56त्न है. प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,355 डगवेल निर्माण शुरू किया जा रहा है। अमृत सरोवर लक्ष्य 992 के मुकाबले 1,254 निर्मित किये जा रहे हैं। माय भारत पोर्टल पर जलदूत पंजीयन का लक्ष्य 1,62,400 तय किया गया था जबकि 2,30,749 स्वयंसेवकों का पंजीकरण किया जा चुका है जो लक्ष्य काफी अधिक है।

जल स्त्रोतों के आसपास ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए 5.5 करोड़ पौधों का रोपण लक्ष्य रखा गया जिसमें जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।तालाब गहरीकरण के दौरान निकली मिट्टी को किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हुआ। मनरेगा परिषद द्वारा इसरो और एमपीएसईडीसी के सहयोग से विकसित यह जीआईएस-आधारित सॉफ्टवेयर जल संरचनाओं के लिए उपयुक्त स्थलों की सटीक पहचान करता है। इसके माध्यम से 76,000 खेत तालाबों के लिए स्थल चयन किया गया। यह तकनीक अन्य राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत बनी।अभियान में 70 हजार से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 341 कलश यात्राएं नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गईं। इनमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रही। अभियान से जुड़े 1000 जल नायक और जल मित्रों का माय भारत पोर्टल पर पंजीयन किया गया। बच्चों और युवाओं में पानी की बचत, पेयजल स्त्रोतों के आस-पास सफाई और स्वच्छ पर्यावरण की भावना को मजबूत करने के लिये रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं हुई। नगरीय क्षेत्रों में व्यापक पौधरोपण की शुरूआत भी की गई। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिये वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण की योजना भी तैयार की गई है। नगर परिषद कटंगी जबलपुर के वार्ड-12 में 100 वर्ष पुरानी बावड़ी में सफाई अभियान चलाया गया। इंदौर के कनाड़ियां में 300 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक माता अहिल्या बावड़ी के जीर्णोद्धार का कार्य जनभागीदारी से किया गया। देवास जिले के बागली की हाथी बावड़ी की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। नगर परिषद बिजावर मे बावड़ी का जीर्णोद्धार कर नया स्वरूप प्रदान किया गया। रतलाम में नगर निगम ने महालक्ष्मी मंदिर के सामने स्थित बावड़ी की साफ-सफाई नागरिकों की भगीदारी से पूरी की। छतरपुर के घुवारा में जर्जर हालत में पहुंच चुकी बावड़ी का सौंदर्यीकरण कर नया स्वरूप प्रदान किया गया।अभियान में 1 लाख जलदूत तैयार करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें प्रत्येक गांव से 2-3 महिला-पुरुषों को शामिल किया गया। ये जलदूत जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और स्थानीय स्तर पर कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान एक जन आंदोलन बन गया।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)- साभार

टीएमसी नेताओं की निर्लज्ज टिप्पणियों से उठा विवाद

ललित गर्ग

कोलकत्ता में कानून की एक छात्रा से सामूहिक दुराचार-गैंगरेप का मुद्दा एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है उतना ही बड़ा नारी उत्पीड़न का मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की अनर्गल एवं निर्लज्ज टिप्पणी स्त्री की मर्यादा, सम्मान एवं अस्मिता के खिलाफ शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण व संवेदनहीन प्रतिक्रिया है। इन नेताओं ने गैंगरेप मामले पर विवादित बयान से राज्य एवं देश में भारी जनाक्रोश पैदा हो गया था। विशेषतः राजनेताओं के बयानों एवं सोच में एक बार फिर शर्मनाक ढंग से पीड़िता पर दोष मढ़ने की बेशर्म कोशिश की गई है। इस मामले में सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी अन्दर एवं बाहर दोनों मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। जहां इस मामले में पार्टी के अन्दर गुटबाजी एक बार फिर सामने आयी है, वहीं भाजपा आक्रामक रूप से ममता सरकार को घेर रही है। टीएमसी की महिला नेत्री महुआ मोइत्रा टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के उन बयानों पर निराशा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इन राजनेताओं के बयान में स्त्री-द्वेष पार्टी लाइन से परे है। यह एक बदतर स्थिति है कि जिस पार्टी के नेताओं ने ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए हैं, उस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला ही है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि ममता बनर्जी जैसी तेजतर्रार मुख्यमंत्री के शासन और नेतृत्व के वर्षों के दौरान टीएमसी के भीतर नारी सम्मान एवं अस्मिता को लेकर संवेदनशीलता लाने और मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। अकसर महिलाएं और महिला राजनेता पुरुष नेताओं के हाथों अश्लील, अभद्र और तौहीन भरी टिप्पणओं की शिकार होती रही हैं। ऐसे बयानों के बावजूद अकसर ये राजनेता किसी कठोर कार्रवाई की बजाय हल्की फुल्की फ़टकार के बाद बच निकलते हैं। ये बयान कभी महिलाओं की बॉडी शेमिंग करते नज़र आते हैं तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को मामूली बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही ये चिन्ताजनक संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में हल्के और आपत्तिजनक बयान देना विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के लिये सामान्य बात है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं) -साभार

मध्यम वर्गीय परिवार नहीं फंसे ऋण के जाल में

प्रहलाद सबनानी

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शीघ्र ही भारत में ऋणदाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। भारत में चूंकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है, अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकता करने की क्षमता भी ऋणदाता में होनी चाहिए अर्थात ऋणदाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्त एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस संदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूक की गई राशि पर भारी मात्रा में ब्याज वसूला जाता है, जिससे युवा ऋणदाता ऋण के जाल में फंस जाते हैं। अतः बैंकों से ली जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है।

> बैंकों से लिए गए ऋण की मासिक किश्त एवं इस ऋणराशि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूककर्ता ऋणदाता से बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है। इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं।

कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके।

ऋणदाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किश्त एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋण खाता यदि गैर निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणदाता द्वारा बैंकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है। इस समझौता प्रस्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋणदाता द्वारा सम्बंधित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को मासिक किश्त एवं ब्याज की राशि को पुनर्निर्धारित किए जाने के सम्बंध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋणदाता ऋण की पूरी राशि, ब्याज सहित, अदा करने में सक्षम नहीं है तो चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बंध में भी समझौता प्रस्ताव दे सकता है। ऋण की राशि अथवा ब्याज की राशि के सम्बंध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त छूट के चलते भविष्य में उस ऋणदाता को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋणदाता को रखना चाहिए। अतः जहां तक सम्भव को ऋणदाता द्वारा समझौता प्रस्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋण की निर्धारित किश्तों एवं ब्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा रास्ता अथवा विकल्प है।

भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है। कई बार मध्यमवर्गीय परिवार एक दूसरे की देखा देखी आपस में होड़ करते हुए भी कई उत्पादों को खरीदने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उस उत्पाद विशेष की आवश्यकता हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए एक पड़ौसी ने यदि अपने चार पहिया वाहन का एकदम नया मॉडल खरीदा है तो जिस पड़ौसी के पास पूर्व में ही चार पहिया वाहन उपलब्ध है वह पुराने मॉडल के वाहन को बेचकर पड़ौसी द्वारा खरीदे गए नए मॉडल के चार पहिया वाहन को खरीदने का प्रयास करता है और बैंक के ऋण के जाल में फंस जाता है। यह नव धनाडय वर्ग यदि बैक से लिए गए ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं कर पाता है तो उस नागरिक विशेष के वित्तीय रिकार्ड पर धब्बा लग सकता है जिससे उसके लिए उसके शेष जीवन में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से पुनः ऋण लेने में कठिनाई आ सकती है। अतः बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों को ऋण की किश्त का समय पर भुगतना करना स्वयं उनके हित में हैं, ताकि भारत में तेज हो रही आर्थिक प्रगति का लाभ आगे आने वाले समय में भी समस्त नागरिक ले सकें। भारत में तो यह कहा भी जाता है कि जिसके पास जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारने चाहिए।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)- साभार

शब्द पहेली - 8415

1	2		3		4			
							5	
6			7				8	9
		10			11	12		
13						14		
		15	16		17			
18	19		20				21	
		22						

बाएँ से दाएँ

1. कृष्ण का एक नाम-4,3
6. धन, संपत्ति-2
7. इस युवती को बयान बदलने पर जेल की सजा हुई है-3
8. विजय, फतह-2
10. आम जनता, लोग-2
11. लाभ, कुल योग-2
13. निर्माण, कृति-3
14. उत्तर-3
15. नष्ट, विनाश-2
17. रुस्तमे हिंद का सिर्फ नाम-2
18. तह, अस्तर-2
20. राजी होना-3
21. अवरोध, रुकावट-2
22. आतंक फैलना-4,3

ऊपर से नीचे

2. भिड़ंत, मुठभेड़-3
3. इस्लामी महीना-4
4. हाथी, गज-4
5. न्यायाधीश-2
6. जोरदार-5
9. लालसी, आकांक्षी, पिपासु-5
10. स्त्रीत्वपूर्ण, स्त्रीय-3
12. वृतांत, घटना-3
16. हल, निष्कर्ष-4
17. राशन, भोजन-4
19. घोड़ा गाड़ी-2
21. रुकावट, अवरोध-3

शब्द पहेली -8414 का हल

अ	प	ना	प	न		प	क	ना
रा	ल		त		ख	स	म	
ज		का	न	न			जो	श
क	ह	र		क	र	ता	र	
ता		ग		छे		र		फ
	ब	र	ग	द		ता	मी	र
द	गा			न	ज	र		मा
	व	त	न		ह		पा	ई
फ	त	ह		स	र	फ	रो	श

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

2 जुलाई 2025 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मिथुन में	कर्क	06.25 बजे से
चंद्र	कन्या में	सिंह	08.41 बजे से
मंगल	सिंह में	कन्या	10.53 बजे से
बुध	कर्क में	तुला	13.04 बजे से
गुरु	मिथुन में	वृश्चिक	15.18 ब.से
शुक्र	वृष में	धनु	17.34 बजे से
शनि	मीन में	मकर	19.39 बजे से
राहु	कुंभ में	कुंभ	21.26 बजे से
केतु	सिंह में	मीन	22.59 बजे से
राहुकाल		मेष	00.29 बजे से
12.00 से 1.30		वृष	02.09 बजे से
बजे तक		मिथुन	04.07 बजे से

बुधवार 2025 वर्ष का 183 वा दिन
दिशाशूल उत्तर **ऋतु** वर्षा।
विक्रम संवत् 2082 **शक संवत्** 1947
मास आषाढ़ **पक्ष** शुक्ल
तिथि सप्तमी 11.59 बजे को समाप्त।
नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी 11.08 बजे को समाप्त।
योग वरीयान 17.47 बजे को समाप्त।
करण वणिज 11.59 बजे तदनन्तर विष्टि 01.00 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 06.6 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 23° 02'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872393
जूलियन दिन 2460858.5
कलियुग संवत् 5125
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2551
हिजरी सन् 1446
महीना मोहर्रम
तारीख 06

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
लाभ	05.54 से	07.22 बजे तक	उद्वेग	05.41 से	07.12 बजे तक
अमृत	07.22 से	08.51 बजे तक	शुभ	07.12 से	08.44 बजे तक
काल	08.15 से	10.19 बजे तक	अमृत	08.44 से	10.16 बजे तक
शुभ	10.19 से	11.47 बजे तक	चर	10.16 से	11.47 बजे तक
रोग	11.47 से	01.16 बजे तक	रोग	11.47 से	01.19 बजे तक
उद्वेग	01.16 से	02.44 बजे तक	काल	01.19 से	02.51 बजे तक
चर	02.44 से	04.12 बजे तक	लाभ	02.51 से	04.23 बजे तक
लाभ	04.12 से	05.41 बजे तक	उद्वेग	04.23 से	05.54 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

न्यूज इन शॉर्ट

जनसुनवाई में कलेक्टर ने 50 आवेदन पत्रों में की सुनवाई

अनूपपुर। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में संपन्न हुई। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने 50 आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय, एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगणों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनी।जनसुनवाई में जैतहरी निवासी रामप्रसाद राठौर ने पट्टे की भूमि का नक्शा-तरमीम कराए जाने, वार्ड नम्बर 01 कोतमा निवासी गोविन्द बैगा ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने, ग्राम सकरा तहसील अनूपपुर की रिया महरा ने जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने, ग्राम मनटोलिया तहसील अनूपपुर की सीता पनिका ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरी किश्त की राशि दिलाए जाने के संबंध में आवेदन दिए।

जमीनी विवाद में गाली-गलौज और धमकी

कोतमा। कोतमा थाना क्षेत्र में बरसात का सीजन आते ही जमीनी विवाद के मामले भी बढ़ जाते हैं। लेदरा गांव में रहने वाले दीपक चौधरी को उसी के चाचा बालचंद के द्वारा विवाद करते हुए अश्लील गाली गलौज कर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। थाने में किए गए शिकायत पर पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के बुलाते जांच की जा रही है।

बिना परमिट चल रही थी स्कूल बस, हाईवे चौकी ने की जब्ती की कार्रवाई

कोतमा। अनूपपुर जिले में स्कूल बसों की जांच के लिए चलाए जा रहे सुरक्षित स्कूल बस अभियान के तहत कोतमा क्षेत्र में संचालित 12 निजी स्कूल बसों पर एक साथ कार्रवाई की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 18,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।कार्यवाही के दौरान बस क्रमांक स्वक्त8क्क2226 बिना परमिट और नंबर प्लेट के चलते पाई गई, जिसे मौके पर जब्त कर हाईवे चौकी पुलिस द्वारा 11,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसके अलावा अन्य स्कूल बसों में भी आवश्यक दस्तावेजों की कमी और नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई की गई।इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के स्कूल आने-जाने में सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक श्री मोती उर रहमान के निर्देशन में चलाया जा रहा यह अभियान 7 दिनों तक लगातार जारी रहेगा।यातायात हाईवे चौकी अनूपपुर द्वारा की जा रही इस कार्रवाई में अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि बच्चों का परिवहन पूर्णतः सुरक्षित और नियमबद्ध हो सके।

धनखोरी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न चोरी मामले में फंसा विक्रेता, दोषी पाए गए विक्रेता के विरुद्ध की गई कार्यवाही

सीधी, ।मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 18 में दिये गए निर्देश की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न इत्यादि के सुरक्षित रख रखाव के लिये समिति प्रबंधक एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओ की जिम्मेदार होती है तथा शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संग्रहित खाद्यान्न इत्यादि की चोरी होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी समिति प्रबंधक एवं विक्रेताओं की मानी जावेगी तथा खुर्दवुर्द स्कंध की वसूली बाजार दर से की जाकर उक्त सामग्री की पूर्ति उपभोक्ताओं को वितरण करने को आदेशित किया गया है।कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान धनखोरी की शिकायत की जाँच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीधी एवं सहकारिता निरीक्षक/ प्रशासक द्वारा संयुक्त रूप की गई, जिसमें विक्रेता की लापरवाही से खाद्यान्न 84.27 क्विं. चावल एवं 18.73 क्विं. गेहूँ का अपयोजन किया जाना पाया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा लालबहादुर सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान धनखोरी को आदेशित किया गया है कि 84.27 क्विं. चावल एवं 18.73 क्विं. गेहूँ बाजार भाव से खरीदकर उपभोक्ताओ को वितरण करे। समिति प्रबंधक समिति से संलग्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों का खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

न बेनिफिकेशन और ना ही डंपिंग एरिया, कम कीमत में उंची कीमत पर विक्रय का खेल

साईंकृपा को नहीं भंडारण की अनुमति, किन नियमों पर हो रहा कोयले का स्टॉक

विजय मत, अनूपपुर

राजन कुमार ,विनय उपाध्याय

साईं कृपा कोल साइडिंग बिजुरी पर उतरने वाले करोड़ों रूपए के काले हीरे का कारोबार बिना भंडारण की अनुमति के संचालित हो रहा है। जहां कम कीमत पर आसपास के कोयला खदानों से तीसरी पार्टी से कोयला की पूर्ति कराते हुए साइडिंग पर डंप कराकर उसे उंची कीमत में विक्रय किया जा रहा है। रेलवे साइडिंग पर भंडारित हो रहे कोयले की लोडिंग और अनलोडिंग को संचालकों ने कानून कायदे से इतर इसे वैध बना दिया है। आश्चर्य है कि कोयले के इस काले खेल में जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से आंखें मूंद ली है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहां भंडारित होने वाला कोयला को किन नियमों के आधार पर भंडारित और परिवहन किया जा रहा है? वहीं प्रदूषण विभाग से लेकर खनिज विभाग द्वारा भी इसमें कोई भूमिका नहीं होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है। जबकि यह साइडिंग न तो बेनिफिकेश है और ना ही डंपिंग एरिया। बावजूद यहां कोयले का नियमित भंडारण किया जा रहा है। दरअसल यहां कोयला भंडारण का काम वर्षो से किया जा रहा है।

रेलवे साइडिंग पर होने वाले कोयले के भंडारण पर शुरूआत में यह लगा कि यहां चंद दिनों के बाद यह कोयले का खेप समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहां एसइसीएल के साथ कोल माफियाओं की सांठगांठ में वर्षो से नियमित कोयले का लोडिंग-अपलोडिंग का खेल खेला जा रहा है। कोयले के हो रहे भंडारण से नगरवासियों को अनचाहा बीमारियों को जन्म दे रहा है। भले ही इस बरसात के मौसम में कोयले की डस्ट नहीं उड़ रही है लेकिन कोयला का मलवा पानी के साथ बहकर आसपास के रहवासियों को संक्रमित बीमारी के आगोश में ले रहा है। और इस बात को यदि जिम्मेदार नकारते हैं तो वह कुछ दिन यहां रहकर देख तो लें।

नियम विरूद्ध हो रहा कोयले का भंडारण

नियमों के अनुसार कोयला खदान से 50 किलोमीटर के भीतर कोयला भंडारण नहीं किया जा सकता है। अगर रेलवे की जमीन पर कोयले के भंडारण की अनुमति मिलती है तो सेवा शर्तो के अनुसार मात्रा के अनुसार 24,48 या 72 घंटे के भीतर उसे खाली किया जाना अनिवार्य होता है। अगर जरूरत पड़े तो सप्ताहभर का समय भी दिया जा सकता है। लेकिन यहां रेलवे की साइडिंग वाली जमीन पर किस नियमों के आधार पर कोयले का भंडारण करने की अनुमति दे रहा है यह समझ से पड़े हैं। जबकि किसी भी खनिज भंडारण के लिए सीटीओ प्रदूषण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन वह सिर्फ भंडारण कर सकता है, साइडिंग का उपयोग या संचालन नहीं कर सकता।

भंडारण की नहीं है अनुमति, पीसीबी ने खनिज के पाले डाला बॉल

सूत्रों की जानकारी के अनुसार साईं कृपा कोल साइडिंग बिजुरी द्वारा भंडारण के लिए पूर्व में खनिज विभाग से अनुमति मांगी थी। लेकिन यहां रेलवे की जमीन होने के कारण खनिज विभाग ने अनुमति देने से मनाही कर दी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संभाग शहडोल के अधिकारी मुकेश श्रीवास्तव का कहना है कि यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, इस सम्बंध में एसइसीएल और खनिज विभाग ही जानकारी दे पाएगा। लेकिन आश्चर्य (सीटीओ) वायु, जल सम्मति का प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग द्वारा ही प्रदाय किया जाता है।

इनका कहना है

यह मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। रेत अलग है माइनिंग डिपार्टमेंट अलग है और कोयले के लिए एसइसील अलग है। इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट और एसइसीएल वाले ही बता पाएंगे।

मुकेश श्रीवास्तव
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी शहडोल संभाग

9 साल से फरार था धोखाधड़ी का आरोपी अनूपपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ से किया गिरफ्तार

विजय मत, अनूपपुर

कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में नौ वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर निवेश के नाम पर ग्रामीणों से लाखों रुपये हड़पने का आरोप है।

पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देशन पर जिले में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी और एसडीओपी सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई अरविंद जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसारए आरोपी रामाधार चौधरी ;45 वर्षद्ध निवासी ग्राम अमगवां थाना जैतहरी ने वर्ष 2016 में फरियादी टीकम प्रसाद रजक से एक निजी फाइनेंस कंपनी श्सृष्टि वेयरश् के नाम पर 5 वर्षों में पैसा दोगुना करने और हर महीने 750 रुपए बोनस देने का लालच देकर 50ए000 रुपए ठगे थे। शिकायत पर कोतवाली में अपराध क्रमांक 167ध्16 धारा 420ए 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में पुलिस अब तक 9 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैए लेकिन रामाधार चौधरी फरार चल रहा था। साइबर सेल की मदद से टीम ने उसे 1 जुलाई 2025 को पेंड्राए छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी में सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह पाटलेए प्रधान आरक्षक शिवशंकर प्रजापतिए विनय बैसए और साइबर सेल से आरक्षक पंकज मिश्रा की अहम भूमिका रही।

जान से मारने की धमकी देने पर दोनो पक्षों पर मामला कायम

उमरिया। चंदिया थाना अंतर्गत तहसील कार्यालय के पास गाली गालौज करते हुए मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत पर पुलिस ने दोनो पक्षों पर मामला कायम कर लिया हैं ।

जानकारी अनुसार चंद्रमणि वर्मा पिता संतोश कुमार बारी उम्र 28 साल ग्राम तेदुआ की शिकायत पर आरोपी प्रमोद तिवारी, गजेन्द्र तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी पर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है।

वही इसी मामले में सच्चिदानंद तिवारी की शिकायत पर आरोपी मुकेश बारी, संतोश बारी, चंद्रमणि बारी , नीलमणि बारी ग्राम तेदुआ पर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है।

बिना नंबर की बाइक से अवैध शराब ले जा रहे दो युवक गिरफ्तार

मोटरसाइकिल सहित 7740 रु. की अंग्रेजी बीयर जब्त

विजय मत, जैतहरी

पुलिस ने रविवार को ग्राम सिंघौरा बाजार के पास कार्रवाई करते हुए बिना नंबर की बाइक में अवैध शराब का परिवहन कर रहे दो युवकों को पकड़ा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वेंकटनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा।

जानकारी के अनुसार अशोक गुप्ता के घर के पास दो युवक काले-नीले रंग की एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल में शराब रखे हुए थे। पूछताछ में चालक ने अपना नाम मुन्ना यादव पिता शंकरलाल यादव उम्र 25 वर्ष और पीछे बैठकर बोरी पकड़े व्यक्ति ने हल्कोई यादव पिता हिसाबी यादव उम्र 26 वर्ष, दोनों निवासी गोपालपुरा थाना कोतवाली, जिला छतरपुर बताया।

पुलिस ने तलाशी के दौरान एक सफेद बोरे से पावर 10000 बीयर केन के 48 नग (24 लीटर), कीमत 5760 रु. और हंटर बीयर की 9 बोतलें (5.85 लीटर), कीमत 1980 रु. बरामद की। कुल जब्त शराब की मात्रा 29.85 लीटर और कीमत 7740 रु. बताई गई है। साथ ही शराब ढोने में प्रयुक्त एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (अनुमानित कीमत 80,000 रु.) भी जब्त की गई।

पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

आधार कैम्पों के माध्यम से अब तक जिले के 5958 नागरिकों के आधार कार्डों में हुए आवश्यक सुधार कार्य

विजय मत, अनूपपुर

कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार जिले के सभी नगरीय निकायों के वार्डो तथा ग्राम पंचायतो में विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ लिए जाने हेतु नागरिकों के आधार कार्ड में आवश्यक सुधार व नए आधार कार्ड बनाए जाने हेतु ग्राम पंचायत व वार्डवार आधार कैम्प का आयोजन 2 जून 2025 से प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक प्रतिदिन अलग-अलग वार्ड व ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। जिसके तहत अब तक 5958 नागरिकों के आधार कार्डों में आवश्यक सुधार कार्य एवं 565 नागरिकों के नए आधार कार्ड बनाए गए हैं।

02 जुलाई को जिले के इन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे शिविर

जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत बरबसपुर, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत केकरिया तथा नगर परिषद बनगवॉ (राजनगर), नगर परिषद अमरकंटक, नगर परिषद डोला, नगरपालिका बिजुरी, नगरपालिका अनूपपुर, नगरपालिका कोतमा के वार्ड नम्बर 07 में एवं नगरपालिका पसान के वार्ड नम्बर 11, नगर परिषद डूमरकछार के वार्ड 05, नगर परिषद बरगवां (अमलाई) के सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 01 में 02 जुलाई को आधार कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

चिकित्सा दिवस पर लीनेस क्लब ने हांकरों को वितरित किया गया रैनकोट

सीधी। शहर में अखबार वितरण करने वाले हाकर को आल इंडिया लीनेस क्लब कामख्या द्वारा रैनकोट वितरण किया गया। रेनकोट पाने के बाद अखबार बांटने वाले गदगद रहे। जिनका कहना था कि बरसात के कारण हम लोगों को परेशानी होती थी लेकिन क्लब के माध्यम से हमें बारिश का छांया जो मिला है उससे हम इस संस्थान के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।

आल इंडिया लिनेस क्लब कामाख्या सीधी द्वारा मंगलवार सुबह 5 बजे पुराने बस स्टैंड में न्यूज वितरकों हॉकरों को रैनकोट वितरित किए गए। वर्षा ऋतु की कठिनाइयों में समाचार वितरकों की सेवा भावना को सम्मान देने हेतु यह पहल की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. बीना मिश्रा अध्यक्ष, संचालन डॉ. सुनीता तिवारी सचिव तथा सहयोग शर्मिला सिंह कोषाध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर इन्द्रवती नाट्य समिति के सचिव नीरज कुन्देर भी उपस्थित रहे।

ओमकार सिंह ने विश्व सैन्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर पुरस्कार जीता

विजय मत, अनूपपुर

नार्वे में आयोजित 55 में सीआईएस एम विश्व सैन्य निशाने बाजी चैंपियनशिप में ओमकार सिंह ने पुरुषों की पिस्टल शूटिंग श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। ओमकार सिंह ने शीर्ष भाग लेने वाली टीमों के निशानेबाजों को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। ओमकार सिंह, एमसीपीओ आई, भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और उन्होंने अपनी सटीक निशानेबाजी तकनीक से 1171 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंचाया। यह उपलब्धि भारतीय नौसेना और देश के लिए गर्व का क्षण है। ओमकार सिंह मध्य प्रदेश के अनुपपुर से हैं। और उन्होंने अपने करियर में कई पदक जीते हैं, जिनमें 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में तीन स्वर्ण पदक शामिल हैं। उन्होंने 50 मीटर पुरुषों की पिस्टल सिंगल्स इवेंट में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और 10 मीटर पुरुषों की एयर पिस्टल में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भारतीय नौसेना ने ओमकार सिंह की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, इतिहास रचा गया!

भारत के लिए पहली उपलब्धि

ओमकार सिंह, एमसीपीओ आई, भारतीय नौसेना को नार्वे में 55वीं सीआईएसएम विश्व सैन्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर नामित किया गया, यह भारत के लिए पहली बार है!÷ ओमकार सिंह की इस उपलब्धि से भारतीय नौसेना और देश का नाम रोशन हुआ है। उल्लेखनीय है की ओमकार सिंह मध्य प्रदेश के अनुपपुर से हैं और एक भारतीय खेल निशानेबाज हैं। वह वर्तमान में भारतीय नौसेना में सेवा कर रहे हैं और सेवा खेलों में भी भाग लेते हैं।

ओम ने देश को दिलाई है कई मैडल

ओमकार सिंह की उपलब्धियां

ओमकार सिंह ने अपने करियर में कई पदक जीते हैं, जिनमें 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में तीन स्वर्ण पदक शामिल हैं। उन्होंने 50 मीटर पुरुषों की पिस्टल सिंगल्स इवेंट में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और 10 मीटर पुरुषों की एयर पिस्टल में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने गुरप्रीत सिंह के साथ मिलकर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल (डबल्स) में भी स्वर्ण पदक जीता। ओमकार सिंह की इस उपलब्धि से भारतीय नौसेना और देश का नाम रोशन हुआ है। उनकी सटीक निशानेबाजी तकनीक और कड़ी मेहनत ने उन्हें विश्व सैन्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर पहुंचाया है।

निरीक्षण

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सीएम के प्रस्तावित कोतमा दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय

विजय मत, अनूपपुर

कलेक्टर हर्षल पंचोली एवं पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान द्वारा आज अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 4 जुलाई 2025 को अनूपपुर जिले के कोतमा में प्रस्तावित दौरे कार्यक्रम के तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोतमा स्थित मैदान का अवलोकन कर मंच निर्माण, सभा स्थल, ग्रीन रूम, प्रदर्शनी स्थल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभा स्थल पर समुचित बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, पेयजल की व्यवस्था, सुविधा गृहों का निर्माण, आम जनों की बैठक व्यवस्था तथा प्रकाश बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर पंचोली ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम से पूर्व सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी आपसी सामंजस्य स्थापित कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा आपातकालीन सेवाओं की तत्परता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया हेलीपैड स्थल चंगेरी का निरीक्षण

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 4 जुलाई को कोतमा में प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रशासनिक तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। इस क्रम में आज कलेक्टर हर्षल पंचोली एवं पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान द्वारा ग्राम चंगेरी में निर्माणाधीन हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री पंचोली ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हेलीपैड पर वीआईपी आगमन को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग एवं आवश्यक सुविधाएँ समयसीमा में पूर्ण की जाएं।

पुलिस अधीक्षक रहमान ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए तथा सुरक्षात्मक इंतज़ामों की समीक्षा की। उन्होंने आगंतुकों की निगरानी, प्रवेश-निकास व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इस दौरान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजीत तिर्की सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यूज इन शॉर्ट

मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, अमरता है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देहदान या अंगदान करने वालों के परिजन को राज्य सरकार 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के कार्यक्रमों में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, बल्कि यह अमरत्व प्रदान करने जैसा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि देहदान अथवा हृदय, लीवर व गुर्दा दान (डोनेट) करने वाले देहदानियों/अंगदानियों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।

एमपीयूडीसी की 'लोगो' तैयार करने के लिये पुरस्कार योजना, श्रेष्ठ 3 'लोगो' को किया जायेगा पुरस्कृत

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत संचालित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी ने क्रिएटिव इनिशिएटिव का शुभारंभ करते हुए एक शानदार 'लोगो' डिज़ाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यह पहल स्र4त्श1 पोर्टल के माध्यम से जन-भागीदारी को प्रेरित करने और कंपनी की शहरी सुधार योजनाओं, शहरों में सीवरेज, जलापूर्ति और अन्य अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के प्रति जागरूकता व पहचान को बढ़ावा देने के लिये की गई है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आम नागरिकों को https://mp.mygov.in/ पोर्टल पर अपना मौलिक डिज़ाइन JPG/PNG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। एमपीयूडीसी द्वारा चयनित विजेताओं के लिये प्रतिष्ठित पुरस्कारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 11 हजार रुपये, द्वितीय 5 हजार और तृतीय स्थान के लिए 2 हजार 500 रुपये की नगद राशि शामिल है। प्रविष्टि की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक तय की गयी है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से एमपीयूडीसी का उद्देश्य न केवल एक आकर्षक ब्रांड पहचान स्थापित करना है, बल्कि यह दर्शाना भी है कि कंपनी किस प्रकार जल प्रदाय परियोजना, सीवरेज परियोजना और नगरों से जुडे अधोसंरचना विकास कार्य करने के लिये कार्यरत है।

आयुक्त जनसम्पर्क ने संचालनालय में किया पौध-रोपण

भोपाल। आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने मंगलवार को जनसम्पर्क संचालनालय परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने अशोक और गुलमोहर का पौधा लगाया। इस अवसर पर जनसम्पर्क के स्टाफ ने आयुक्त जनसम्पर्क को उनके जन्मदिवस के अवसर पर बधाई दी। इस दौरान अपर संचालक जी.एस. वाधवा, अपर संचालक संजय जैन एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

खाद्य विभाग की कार्यशाला 2-3 जुलाई को

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 02 दिवसीय कार्यशाला 2 और 3 जुलाई 2025 को पलाश रेसीडेंसी भोपाल में आयोजित की जा रही है। प्रशिक्षण में खाद्य विभाग, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन एवं मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जिले एवं प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सहभागिता करेंगे। कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त कर्मवीर शर्मा एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि, उन्हें नवीनतम नियमों, नीतियों, नवाचार, चुनौतियों तथा विभागीय कार्यप्रणालियों की जानकारी देना, जिसमें मिलिंग, भंडारण, उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली , ई ऑफिस, ई सीआर,आईगोट जैसे विषय शामिल रहेंगे। साथ ही अधिकारी/कर्मचारियों की समस्या और सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। विभाग से संबंधित केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्राइवेट एजेंसी एवं ITC और Zomato कंपनियों के अधिकारियों द्वारा भी कार्यक्षमता व कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 9वीं से कॉलेज तक के लिए विद्यार्थियों को करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन

भोपाल। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कक्षा 9वीं से महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्हें केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होता है और जिनकी निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है,उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP website https://scholarships.gov.in) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR - One Time Registration) करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार OTR नंबर प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए पृथक से पुनः वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 से पूर्व करना अनिवार्य है।

लोक निर्माण से लोक कल्याण: पौधारोपण स्थल की जियोमैपिंग कर सैटेलाइट से की जायेगी मॉनिटरिंग

पौधरोपण पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य देने का संकल्प : सिंह

- मिट्टी से सरोवर तक-वृक्ष से वर्षा तक लोक निर्माण विभाग की नई सोच
- लोक निर्माण विभाग ने एक दिन में लगाए 2 लाख से अधिक पौधे
- पौधों के विकास की निगरानी का अभिनव प्रयोग

विजय मत, भोपाल

हरित मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने मंत्री राकेश सिंह की अगुवाई में ऐतिहासिक पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस एक दिन में विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 2 लाख से अधिक पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो सतत विकास और हरियाली के प्रति विभाग की सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा की ÷पौधरोपण सिर्फ औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य देने का हमारा दृढ़ संकल्प है।÷ उन्होंने कहा कि प्रारंभ में जहाँ 1 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया था, वहीं विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों की प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्साह के चलते यह संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक पौधों तक पहुँच गई। यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि हरित मध्यप्रदेश की दिशा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि है जो सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाती है।

मंत्री सिंह ने कहा कि इस पौधारोपण को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ा गया है। प्रत्येक पौधे की सैटेलाइट मॉनिटरिंग की योजना बनाई गई है, जिसमें अहमदाबाद स्थित भास्कराचार्य संस्थान का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके माध्यम से पौधों की वृद्धि और संरक्षण की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। यह वृक्षारोपण सड़क किनारे, विभागीय भवन परिसरों, तालाबों एवं सार्वजनिक स्थलों पर किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'हरित भारत' के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पर्यावरण-अनुकूल विकास के विजन ने मध्यप्रदेश में वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण को एक जनआंदोलन का रूप दिया है। उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, ऐसे समय में यह पहल प्रेरक उदाहरण बनेगी। उन्होंने आमजन, विभागीय अधिकारियों, अभियंताओं और उनके परिवारों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।

मंत्री सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग अब केवल भौतिक संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, हरित तकनीकों के उपयोग और पारिस्थितिकी संतुलन को अपनी कार्यशैली में प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण केवल एक नारा नहीं है, बल्कि विभाग की मूल कार्यनीति है, जिसमें अब पर्यावरणीय संतुलन को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।

शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने विशेष अभियान 15 तक: राजपूत

विजय मत, भोपाल

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को राशन वितरण करने के लिये हितग्राहियों की ई-केवायसी करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया है कि शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने तथा मृत तथा अपात्र एवं अस्तित्वहीन हितग्राहियों का मौके पर सत्यापन के बाद उनका नाम हटाने के लिये 1 से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।

गौरतलब है कि अभी तक कुल पात्र हितग्राही 5 करोड़ 32 लाख 42 हजार में से 4 करोड़ 75 लाख 66 हजार हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जा चुके हैं। इनमें 2 लाख 36 हजार हिताग्राहियों के नाम विलोपित किये गये हैं। इनमें से 54 लाख 40 हजार की ई-केवायसी किया जाना शेष है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ई-केवायसी कराने के लिये जून माह में ई-केवायसी से शेष परिवारों को ई-केवायसी के बाद राशन वितरण की व्यवस्था की गई है।

ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों का घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिये वार्ड प्रभारी/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक की ड्यूटी लगाने के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं। ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकान/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर चस्पा की जाएगी।

मौके पर उपलब्ध एवं पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर जाकर अथवा ÷मेरा राशन÷ एप पर फेस एथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवायसी करने के लिये अवगत कराने और हितग्राही के आधार नंबर में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण होने एवं बायोमेट्रिक डाटा अपडेट न होने पर आधार केम्प में जाकर डाटा अपडेट कराने के निर्देश दिये गये हैं। पात्र हितग्राही द्वारा उचित मूल्य दुकान पर ई-केवायसी कराने पर आगामी दिवस में पात्रतानुसार राशन प्राप्त किया जा सकेगा।

कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम/वार्ड में सत्यापन के लिये नियत दिनांक की सूचना एक दिन पूर्व हितग्राहियों को विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई जाए। ई-केवायसी की मॉनीटरिंग के लिये अनुभाग एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जिसमें सत्यापन दल द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी ली जाए।

सर्वोदय गृह निर्माण समिति के आवंटियों की समस्या का करें निराकरण: कृष्णा गौर

- पटेल नगर कॉलोनाईजर के विरूद्ध एफआईआर कराने के निर्देश

विजय मत, भोपाल

रायसेन रोड स्थिति पटेल नगर कालोनी के कॉलोनाईजर के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। प्रकरण दर्ज कराने के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर मंगलवार को मंत्रालय में गोविंदपुरा क्षेत्र की सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था, अग्रोहा गृह निर्माण समिति, कुंजन गृह निर्माण समिति, पटेल नगर कॉलोनी और रहवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रहीं थी।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने पटेल नगर कॉलोनी में स्कूल, खेल मैदान, पार्क आदि के लिए छोड़े गए भू-खंडों को नगर निगम के लिए सौपने के स्थान पर कॉलोनाईजर ने इस कॉलोनी के प्राईमरी स्कूल के एक भू-खंड को निजी तौर पर विक्रय कर दिया। नगर निगम के स्वामित्व के इन भू-खंड को विक्रय करने का अधिकार कॉलोनाईजर को नहीं है। कॉलोनाईजर द्वारा किया गया यह कृत्य आपराधिक है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्यमंत्री गौर ने नगर निगम के अधिकारियों को कॉलोनाईजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉलोनाईजर द्वारा विक्रय किए गए भू-खंड की रजिस्ट्री को शून्य कराने की प्रक्रिया भी शुरू करें। इसके साथ ही कॉलोनाईजर अन्य ओपन एरिया को विक्रय नहीं कर सके इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि पटेल नगर कॉलोनी 1960 के दशक में विकसित की गई थी। इसमें 700 से अधिक प्लाट हैं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था खजूरी भोपाल में आवंटियों और सहकारी संस्था के पदाधिकारियों के बीच कॉलोनी के विकास कार्यो को लेकर आ रही समस्या के निराकरण के लिए और समिति में पिछले वर्षों में हुई कार्यवाही से आवंटियों को उनका वास्तविक हक दिलाने के लिए संयुक्त आयुक्त, सहकारिता भोपाल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप आयुक्त सहकारिता से कहा कि वह आवंटियों और सहकारी संस्था के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में अग्रोहा गृह निर्माण समिति नर्मदापुरम रोड की सीवेज और सड़क निर्माण के लिए रहवासियों के साथ समन्वय कर अधिकारियों को कार्य करने के लिए कहा। इसी प्रकार कुंजन गृह निर्माण संस्था नर्मदापुरम रोड में फेस-1 और फेस-2 में सीवेज और रोड के विकास के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी, कॉलोनियों के रहवासी और सहकारी समितियों के पदाधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश के शहरी मार्गों पर 582 इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना

भोपाल। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर में छूट और अनुदान दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस सेवा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में इंदौर में शहरी मार्गों पर 80 इलेक्ट्रिक बसों को संचालन किया जा रहा है। फेम योजना के अंतर्गत 40 और अमृत योजना 1.0 में 40 बसें संचालित हो रही हैं। ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 6 शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिये प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था, जिसे केन्द्रीय शहरी मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति मिल गयी है। इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 एवं उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव है।

एमपी ओपन बोर्ड ने जारी किया रूक जाना नहीं का परिणाम, आ लौट चलें योजना के नतीजे भी घोषित

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल बोर्ड की ओर से रूक जाना नहीं और आ लौट चलें योजना का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, और 12वीं जून परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया गया है। इन कक्षाओं के जो भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ओपन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpsos.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। एमपीएसओएस टाइम टेबल 2025 के अनुसार, 10वीं की ओपन स्कूल परीक्षा 2 जून से 14 जून, 2025 तक, जबकि कक्षा 12वीं ओपन स्कूल परीक्षा 2 से 20 जून तक की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 4 को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वितरित करेंगे लैपटॉप

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम

विजय मत, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 4 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रति विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की राशि लैपटॉप क्रय करने के लिये उनके बैंक खाते में अंतरित करेंगे। इस वर्ष 94 हजार 234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिये 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रूपये की राशि दी जा रही है।

कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक सहभागिता करेंगे। प्रदेश में पिछले वर्ष 2023-24 में 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपये की राशि अंतरित की गयी थी। प्रदेश में यह योजना वर्ष 2009-10 से संचालित हो रही है। पिछले 15 वर्षों में इस योजना में 4 लाख 32 हजार 16 विद्यार्थियों के बैंक खातों में एक हजार 80 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप के लिये अंतरित की जा चुकी है।

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का कर दिया है विनष्टीकरण, सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश

विजय मत, ब्यूरो, जबलपुर

यूनियन कार्बाइड के 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है। ये जानकारी हाईकोर्ट में सरकार की तरफ हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की युगलपीठ को दी गई। यूसीआईएल से 19.157 मीट्रिक टन अतिरिक्त जहरीला कचरा एकत्र किया गया है, जिसका विनष्टीकरण 3 जुलाई 2025 तक कर दिया जाएगा। बताया गया कि केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में जहरीले कचरे का विनष्टीकरण किया गया है।

गौरतलब है कि भोपाल निवासी आलोक प्रभाव सिंह द्वारा साल 2004 में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड कंपनी से हुए जहरीले गैस रिसाव में लगभग 4 हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में करीब 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरा पड़ा है। याचिका में जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान लेकर कर रहा है। याचिका दायर किए हुए 20 साल से समय गुजर जाने के बावजूद भी जहरीले कचरे का विनिष्टीकरण नहीं किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था। जहरीले कचरे का विनिष्टीकरण के संबंध में हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए थे।

विजय मत एंकर | **प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान**

3 किलोवॉट रूफटॉप सोलर लगाने पर 78 हजार रूपये की मिलेगी सब्सिडी : एमडी बैंस

विजय मत, भोपाल

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएनएल) के एमडी अमनवीर सिंह बैंस ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में ÷प्रधानमत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली÷ योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिये शासन प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने पर शासन द्वारा 78 हजार रूपये की सब्सिडी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। एमडी बैंस ने जनता से अपील की है कि पीएम सूर्य घर पोर्टल पर अधिक से अधिक आवेदन करें। प्रदेश में लगभग 850 वेंडर इस कार्य में संलग्न किये गये हैं, आवेदक स्वयं उसमें से आप वेंडर का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदेश के क्लीन एनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) के क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश को अव्वल बनाने में अपना योगदान दें।

एमडी बैंस ने बताया कि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और नॉलेज पार्टनर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर ने साथ मिलकर मंगलवार को पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्यप्रदेश में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिये कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मीडिया को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों, इसमें मौजूद संभावनाओं और मध्यप्रदेश को सौर ऊर्जा संपन्न बनाने के प्रयासों की जानकारी दी गई।

एमडी बैंस ने कार्यशाला में सौर ऊर्जा को लेकर सरकार के विजन, प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति, पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया और प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में MPUVNL की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ÷पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवासीय घरों की छतों पर सोलर लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले दो किलोवॉट के लिए प्रति किलोवाट 30 हजार रुपये और तीसरे किलोवॉट के लिए 18 हजार रुपये सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। इस तरह से तीन किलोवाट के रूफटॉप सोलर के लिए कुल 78 हजार रुपये की सब्सिडी उपलब्ध हैं।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर के लाभों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, ÷इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं। इस प्रोजेक्ट से ग्रिड पर उपभोक्ता की निर्भरता कम होती है। इससे दिन के समय उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध होती है। छतों पर सोलर सिस्टम को लगाने में उपभोक्ताओं की जितनी राशि व्यय होती है, वह पांच से छह वर्ष में रिकवर हो जाएगी। उसके बाद सोलर सिस्टम से बाकी समय में बिजली की बचत के माध्यम से लाभ होगा।

मंत्री संपतिया उइके मामले में पटवारी बोले-

1 हजार करोड़ की जांच 4 दिन में पूरी कैसे, सीबीआई जांच की मांग

विजय मत, भोपाल

मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री संपतिया उइके के 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप मामले में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जांच को लेकर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है, जो देश और दुनिया को स्पष्ट दिख रहा है। पटवारी ने कहा कि 21 तारीख को जांच के आदेश दिए जाते हैं और 25 तारीख को जांच पूरी हो जाती है। 4 दिनों में एक हजार करोड़ रुपए की जांच समाप्त हो जाना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने कहा है कि मामले में प्रधानमंत्री को वह पत्र लिखेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे।

पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि वे जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखिंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के 60त्न कमीशन का मामला है। इसका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। मंत्री को तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक नेशनल टीम भेजकर इसकी जांच करनी चाहिए। साथ ही इसकी सीबीआई जांच भी कराई जाना चाहिए।

पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का दावा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खाने का काम कर रही है। बीजेपी के नेता ही खा सकते हैं, दूसरों को उसमे भी कोई छूट नहीं है। खांऊगा ही और हम ही खाएंगे, ये भाजपा का नया नारा है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा देश बनाने की बात कही थी, जिसमें कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। पटवारी ने कहा कि 21 तारीख को जांच के आदेश दिए जाते हैं और 25 तारीख को जांच पूरी हो जाती है। ये इसलिए की मंत्री बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है।

इसलिए कि बीजेपी की जांच एजेंसी है। क्या ये मोदी का नया भारत है, न खांऊगा न खाने दूंगा। अगर विपक्ष का हो तो छीछालेदर और अपना हो तो उसमे शहद डाल दो। अगर ये देश के लिए हित में नहीं है, तो हमे लड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने भी मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर हमला बोला है।

मुंबई के लिए ही खेलेंगे यशस्वी, एनओसी वापस ली

मुम्बई, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आने वाले समय में भी मुम्बई की ओर से खेलते रहेंगे। यशस्वी ने मुम्बई क्रिकेट बोर्ड (एमसीए) से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा था वह उन्होंने वापस ले लिया है। यशस्वी ने हाल ही में कहा था कि वह गोवा की ओर से खेलना चाहते हैं जिससे लिए उन्होंने एमसीए से एनओसी देने का अनुरोध किया था पर बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। एमसीए ने शुरू में एनओसी के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। यशस्वी गोवा की टीम से जुड़ने के साथ उसके कप्तान बनना चाहते थे। एमसीए की शीर्ष परिषद ने इस युवा बल्लेबाज के एनओसी वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

वहीं एमसीए ने बल्लेबजा पृथ्वी शॉ के दूसरे राज्य के लिए खेलने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनको एनओसी देना मंजूर कर लिया है। यशस्वी आजकल भारतीय टीम के साथ ही इंग्लैंड दौरे पर हैं। वहीं खराज फार्म से गुजर रहे पृथ्वी अब अपनी गलतियों को सुधारकर नई शुरुआत करना चाहते हैं।

पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 से पाकिस्तान का बाहर होना तय

नई दिल्ली, एजेंसी

बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 9 सितंबर तक पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 खेला जाएगा। भारत की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को शामिल किये जाने की कोई संभावना नहीं हैं। वहीं हॉकी इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में सरकार के साथ बातचीत जारी है और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा पर इस अधिकारी के अनुसार जिस प्रकार के तनावपूर्ण संबंध दोनो देशों के बीच हैं उसमें पाक का बाहर होना तय है। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम को बाहर करने की मांग तेज हो गयी है। वहीं हॉकी इंडिया के एक अधिकारी ने एशिया कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर कहा, हम सरकार के संपर्क में हैं और हम उसके निर्देशों का पालन करेंगे। मौजूदा स्थिति के अनुसार मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही कहा कि हम सरकार के आदेशों के अनुसार ही काम करेंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बराबरी के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

बर्मिंघम, एजेंसी

भारतीय भारतीय क्रिकेट टीम यहां बुधवार से मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शुरु हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में जीत के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम को पहले टेस्ट में पांच शतक लगाने के बाद भी खराब फील्डिंग के कारण हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उसका लक्ष्य इस मैच में अपनी कमजोरियों को दूर करना रहेगा। पहले टेस्ट में भारतीय टीम की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही सफल रहे थे। वहीं अन्य गेंदबाज विफल रहे थे जिसका भी नुकसान उसे उठाना पड़ा था। पांच मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम 1-0 से पीछे हैं। ऐसे में उसके लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। उसे सीरीज में बराबरी के लिए इसे जीतना ही होगा। इस मैच के लिए मेजबान टीम ने कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं भारतीय टीम बदलावों के साथ उतरेगी पर क्या बदलाव होंगे ये

मैच से पहले ही पता चलेगा क्योंकि भारतीय टीम ने अभी तक अपने अंतिम ग्यारह खिलाड़ियों की घोषणा नहीं की है। भारतीय टीम के मुख्य तेज गेंदबाज बुमराह को इस मैच में आराम दिया जाना है। ऐसे में उनकी जगह पर बांए हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह या आकाशदीप सिंह को शामिल किया जा सकता है। वहीं ऑलराउंडर स्थान कुलदीप यादव को अवसर मिलने की संभावना नहीं है। ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर पहले टेस्ट में प्रभावित नहीं कर पाये थे, ऐसे में उनकी जगह युवा नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में शामिल किय जा सकता है।

बर्मिंघम में गर्म मौसम और सूखी पिच को देखते हुए इसमें स्पिनरों को सहायता मिल सकती है। ऐसे में भारतीय टीम दो स्पिनरों को अंतिम ग्यारह में जगह दे सकती है। ऐसे में अनुभवी रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर में से दो को टीम में जगह मिल सकती है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसर टीम प्रबंधन कुलदीप की जगह वॉशिंगटन सुंदर को शामिल कर सकता है।

एजबेस्टन क्रिकेट मैदान की बात करें, तो मैच की शुरुआत में पिच से गति और उछाल हासिल हो सकता है। ऐसे में सलामी बल्लेबाजों के लिए तेज गेंदबाजों का सामना करना आसान नहीं होगा। शुरुआत के दो दिन भले ही ड्यूक गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन तीसरे और चौथे दिन पिच बल्लेबाजी के लिए आसान हो सकती है। अगर बादल छाए रहे, तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। यहां मुकाबले के दूसरे और तीसरे दिन पिच नरम हो जाती है, जबकि चौथे और पांचवें दिन पिच पर दरारें और खुरदरे पैच नजर आने लगते हैं, जिससे स्पिनरों को सहायता मिलती है। मौसम विभाग के अनुसार मैच के पहले दिन बारिश की आशंका है।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), साईं सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, नितीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अभिमन्यु ईश्वरन, ।

इंग्लैंड अंतिम ग्यारह- बेन स्टोक्स (कप्तान), जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग और शोएब बशीर।

भारतीय टीम के अगले माह बांग्लादेश दौरे पर जाने की संभावनाएं नहीं

बीसीबी बोली, अभी संभव नहीं तो भविष्य में करेंगे इंतजार

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम को अगले माह तीन एकदिवसीय और इतने ही टी20 मैचों के लिए बांग्लादेश दौरे पर जाना है पर मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए ये दौरा शायद ही हो पाये। बांग्लादेश में जिस प्रकार के खराब हालात हैं उसको देखते हुए केन्द्र सरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को इस दौरे के लिए शायद ही अनुमति दे। इसका अंदेशा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को भी है। इसी को देखते हुए बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि आगामी सीमित ओवरों की सीरीज को लेकर बीसीसीआई अपनी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है। अमीनुल के अनुसार अगर भारतीय टीम अगस्त में नहीं आती तो वे भविष्य में भारतीय टीम के आने का इंतजार करेंगे। बीसीबी प्रमुख ने कहा कि हमारी बीसीसीआई के साथ बातचीत चल रही है। यह जरूरी नहीं कि हम अगस्त या सितंबर में ही सीरीज कराएं, हम बातचीत कर रहे हैं कि सीरीज अगर अभी संभव नहीं है तो इसे आने वाले समय में किस प्रकार आयोजित किया जा सकता है। इससे पहले दोनो देशों के बीच टी20ढ्ढ सीरीज पिछले साल 2024 में हुई थी, जब बांग्लादेश की टीम भारती दौरे पर आई थी।

बुमराह को मिलेगा आराम, कुलदीप पर संशय, सुंदर को मिल सकती है जगह

दूसरे टेस्ट में नई रणनीति और बदलावों के साथ उतरेगी भारतीय टीमः डोशेट

बर्मिंघम, एजेंसी

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां बुधवार से शुरु हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए अभी तक अपनी टीम घोषित नहीं की है। यहां के एजबेस्टन मैदान पर होने वाले इस मैच को लेकर अनुमान है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा और स्पिनर कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक अंतिम ग्यारह में शामिल किया जाएगा। वहीं भारतीय

टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कहा कि भारतीय टीम नई रणनीति से उतरेगी। डोशेट ने कहा है कि दूसरे टेस्ट में कम से कम दो बदलाव किये जाएंगे। ऐसे में टीम बर्मिंघम टेस्ट में नए संयोजन के साथ उतर सकती है। डोशेट ने बताया कि तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को बर्मिंघम टेस्ट में आराम दिया जाएगा। कार्यभार प्रबंधन के तहत ही उन्हें यह ब्रेक दिया जा रहा है हालांकि वह लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे टेस्ट में वापसी करेंगे। बुमराह ने पहले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया था पर फिटनेस बनाये रखने उन्हें आराम दिया जा रहा है।

डीविलियर्स बोले इस प्रकार सभी मैच खेल सकते हैं बुमराह

जोहांसबर्ग, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत ही इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों में ही उतारा जाना तय हुआ है। ऐसे में टीम इंडिया का गेंदबाजी आक्रमण प्रभावित होगा। इसी को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डी विलियर्स ने सुझाव दिया है कि उन्हें बड़ी सीरीजों में खेलना चाहिये और कम महत्वपूर्व सीरीजों में आराम दिया जाना चाहिये ताकि उनकी फिटनेस भी

बनी रही। डिविलियर्स ने कहा कि हमारी टीम के तेज गेंदबाज डेल स्टेन यही तरीका अपनाते थे और हर बड़ी सीरीज खेलते थे। डिविलियर्स के अनुसार स्टेन का ये तरीका बुमराह को भी अपनाना चाहिये क्योंकि भी भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड सीरीज से अधिक जरुरी अभी कुछ नहीं है। भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 0-1 से पीछे हैं। ऐसे में अगर बूमराह सभी मैच नहीं खेलते हैं तो उसे नुकसान होगा। अब देखना है कि भारतीय टीम प्रबंधन डिविलियर्स के इस सुझाव को मानता है या नहीं। इंग्लैंड दौरा शुरू होने से पहले ही साफ हो गया था कि बुमराह इस सीरीज में तीन मैच ही खेलेंगे। वहीं अब भारत पहला मैच हारकर पिछड़ रहा है, ऐसे में टीम को बुमराह की काफी जरूरत है।

बिजनेस

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 26 पैसे की बढ़त के साथ ही 85.50 पर बंद हुआ। वहीं शुरुआती कारोबार में 42 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.34 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर के कई महीने के निचले स्तर पर पहुंचने और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख से रुपये को बल मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 85.66 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 85.34 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 42 पैसे की बढ़त को बताता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.76 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.17 फीसदी की गिरावट के साथ 96.71 पर आ गया।

एनएमडीसी ने लगातार दूसरी बार किया कटौती का ऐलान

नई दिल्ली। सार्वजनिक खनन कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार, 1 जुलाई को 2.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट की वजह कंपनी द्वारा लगातार दूसरे महीने अपने प्रमुख उत्पादों की कीमतों में की गई कटौती है। एनएमडीसी ने लम्प ऑर की कीमत 600 रुपए से घटाकर 5,700 रुपए प्रति टन और फाइंस की कीमत 500 रुपए से घटाकर 4,850 रुपए प्रति टन कर दी है।

शेयर बाजार हल्की बढ़त पर बंद

सेंसेक्स 91 अंक चढ़कर 83,697 पर बंद, निफ्टी 25,540 के पार

मुम्बई, एजेंसी

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हल्की बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी बाजार ज्यादा ऊपर नहीं आ पाया। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 90.83 अंकों की बढ़त के साथ ही 83,697.29 अंकों पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी 24.75 अंकों की बढ़त के साथ ही 25,541.80 अंकों पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 13 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ ऊपर आकर बंद हुए, जबकि बाकी की सभी 17 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ ही नीचे बंद हुए। निफ्टी की 50 में से 24 कंपनियों के

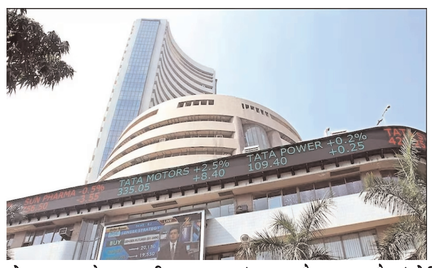

शेयर बढ़त के साथ ही लाभ पर बंद हुए और बाकी की 26 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ ही नीचे आये। आज सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल बीईएल के शेयर सबसे ज्यादा 2.51 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए जबकि एक्सिस बैंक के शेयर आज सबसे ज्यादा 2.13 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की अन्य कंपनियों में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 1.84 फीसदी, एशियन पेंट्स 1.18 फीसदी, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.10 फीसदी, कोटक महिंद्रा बैंक 0.93 फीसदी, एचडीएफसी बैंक 0.60 फीसदी, टाइटन 0.30फीसदी, भारती एयरटेल 0.29 फीसदी, भारतीय स्टेट बैंक 0.04 फीसदी और इंफोसिस के शेयर 0.04 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए।वहीं दूसरी ओर आज , टेक महिंद्रा 1.05 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक 0.95 फीसदी, टीसीएस 0.89 फीसदी, एनटीपीसी 0.70 फीसदी, पावरग्रिड 0.67 फीसदी, एचसीएल टेक 0.60 फीसदी, टाटा मोटर्स 0.60 फीसदी, सनफार्मा 0.57 फीसदी, अडाणी पोर्ट्स 0.37 फीसदी, आईटीसी 0.31 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.25 फीसदी, मारुति सुजुकी 0.23 फीसदी नुकसान के साथ बंद हुए। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार हरे निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में ऑटो और आईटी सेक्टर में खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स 188.66 अंक बढ़कर 83,795.12 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 54.80 अंक बढ़कर 25,571.85 पर कारोबार कर रहा था। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी बाजार के नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के साथ, ग्लोबल इक्विटी बाजार का मूड सकारात्मक है और पश्चिम एशियाई भू-राजनीति अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा नहीं है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक 51.95 अंक बढ़कर 57,364.70 पर कारोबार कर रहा था।

दिल्ली में 1 जुलाई से तय समय से अधिक पुराने वाहनों पर नया नियम हुआ लागू

- 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा

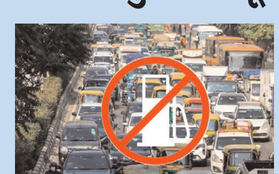

नई दिल्ली, एजेंसी

दिल्ली में मंगलवार 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अब शहर के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। यह फैसला राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए लागू किया गया है। इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर एआई आधारित ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर वह कितने साल पुराना है बता देते हैं। तय सीमा से अधिक पुराने वाहन की पहचान होने पर उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक पेट्रोल पंप पर अधिकारी तैनात रहेंगे। सभी पंपों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार करें और उनका रिकॉर्ड रखें। अगर कोई वाहन मालिक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, वाहन जब्त भी किया जा सकता है। दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपए जुर्माना तय किया गया है, सार्वजनिक

कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर के साथ खनिज क्षेत्र में करेंगे काम

- दोनों ने गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली, एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने मंगलवार को महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर के साथ एक समझौता किया है। सीआईएल ने बीएसई को दी सूचना में बताया कि दोनों कंपनियों ने तांबा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए सोमवार को गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले सीआईएल और आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों के विकास पर सहयोग एवं सहभागिता के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज रेत और दुर्लभ खनिजों सहित महत्वपूर्ण खनिजों की परस्पर सहमत परिसंपत्तियों का विकास करना है। सीआईएल की घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे खनिज तेजी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल हैं। पवन टर्बाइन और बिजली तंत्र से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी निर्माण तक इनका उपयोग किया जाता है।

होटल-रेस्टोरेंट वालों को मिलेगी राहत

1 जुलाई से 58 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर

नई दिल्ली, एजेंसी

तेल कंपनियों ने 1 जुलाई से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव कम कर दिए हैं। हर महीने की पहली तारीख को कंपनियां सिलेंडर के दाम अपडेट करती हैं और इस बार दाम में 58.50 की कटौती की गई है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत इस प्रकार है- दिल्ली में अब 19 किलो का सिलेंडर 1723.50 की जगह 1665 में मिलेगा, नोएडा में 1747.50, कोलकाता में 1826

की जगह 1769, मुंबई में 1674.50 से घटकर 1616 और चेन्नई में यह सिलेंडर 1881 की जगह 1823.50 रुपए में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर के सस्ते होने से होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यापारियों को राहत मिलेगी क्योंकि इन जगहों पर गैस की खपत ज्यादा होती है। आईओसीएल के आंकड़ों के अनुसार लगातार चौथे महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं लगातार चार महीनों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में करीब 140 रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी है। आईओसीएल के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 138 रुपए की गिरावट देखी गई है। जबकि कोलकाता में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 144 रुपए दाम कम हुए हैं। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो यहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 139 रुपए की गिरावट देखी गई है।

मारुति और टोयोटा करेगी कई एसयूवी लांच

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी कंपनी और जापान की दिग्गज टोयोटा आने वाले महीनों में भारत में कई नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा को भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है। इस एसयूवी को कंपनी ने 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भी शोकेस किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ई-विटारा में दो बैटरी पैक के विकल्प मिलेंगे और यह एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है। यह एसयूवी भारतीय ग्राहकों के लिए किफायती इलेक्ट्रिक विकल्प बन सकती है। इसके अलावा मारुति अपनी नई मिड-साइज एसयूवी भी उतारने जा रही है, जिसका कोडनेम वाय17 है और नाम मारुति एस्कुडो रखा जा सकता है।

वित्त वर्ष 26 में तेजी से बढ़ेगा भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टरः रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

मोतीलाल ओसवाल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और मजबूती से आगे बढ़ेगा। अप्रैल-जून की पहली तिमाही में प्रति कमरे आय)में 11-12 फीसदी की सालाना ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। यह बढ़त औसत कमरे का किराया)और घरेलू यात्रा की मांग में उछाल की वजह से है। वित्त वर्ष 25 में होटल कंपनियों की आमदनी में 18 फीसदी और ऑपरेटिंग मुनाफे में 20 फीसदी की वृद्धि देखी गई। धार्मिक पर्यटन, शादियों, लाइव इवेंट्स और कॉर्पोरेट आयोजनों ने होटल बुकिंग को मजबूती दी है। सरकार की प्रसादऔर स्वदेश दर्शन योजनाओं से अयोध्या, तिरुपति और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों में होटल चेन का तेज़ विस्तार हो रहा है।

टूरिस्ट परमिट की आड़ में चल रहा सवारी बस घोटाला

रात के अंधेरे में दौड़तीं दर्जनों बसें, नियमों की उड़ रही धज्जियां

विजय मत, शहडोल।
जिले में टूरिस्ट परमिट की आड़ में यात्री परिवहन का अवैध कारोबार जोरों पर है। प्रतिदिन दो दर्जन से अधिक बसें शहडोल जिले से होकर सवारियों को ढोती हुई गुजर रही हैं, लेकिन न तो परिवहन विभाग इसकी सुध ले रहा और न ही पुलिस महकमा जांच करने की जहमत उठा रहा है। ये बसें रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शहर की सीमा में प्रवेश करती हैं और विभिन्न रूटों पर रवाना हो जाती हैं।

नियमों की खुलेआम अव्हेलना

बता दें कि कि ये बसें नागपुर, रीवा, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, बनारस, जनकपुर और इंदौर जैसे शहरों के लिए यात्रियों को ढो रही हैं। जबकि टूरिस्ट परमिट केवल पर्यटन, विवाह या विशेष आयोजनों के लिए ही वैध होता है। इन बसों का नियमित रूप से सवारी ढोना, नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। टूरिस्ट परमिट के तहत बसों को न बस स्टैंड में प्रवेश की अनुमति है और न ही सवारियां बैठाने की।

सांठगांठ से चल रहा खेल

स्थानीय सूत्रों की मानें तो परिवहन विभाग और पुलिस की मिलीभगत के चलते यह खेल जारी है। अधिकारियों की नजर के सामने ये बसें रोजाना शहर से गुजरती हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। परिवहन और पुलिस विभाग की चुप्पी इस पूरे प्रकरण पर सवालिया निशान खड़े करती है।

सवालों के घेरे में परिवहन विभाग

एनएच-43 सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर परिवहन व यातायात पुलिस तैनात रहती है, फिर भी कार्रवाई का अभाव है। क्या अब तक किसी ने इन बसों के परमिट और उनकी मंजूरी की जांच की? बीते कई महीनों से इस गोरखधंधे पर कोई अंकुश नहीं लग सका है।

दुर्घटना की स्थिति में कौन जिम्मेदार

इन बसों की यदि किसी दुर्घटना में यात्रियों को नुकसान होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? जब परमिट और टिकट में मेल नहीं है, तो बीमा कंपनियां भी मुआवज़ा देने से इनकार कर सकती हैं। इससे आम यात्रियों की सुरक्षा और अधिकार दोनों खतरे में हैं।

चेक पोस्ट पर खुलेआम सौदेबाज़ी

मप्र-छग व मप्र-यूपी सीमा पर बने चेक पोस्टों पर भी 24 घंटे स्टाफ तैनात है, लेकिन वहां भी परमिट की जांच के बजाय सौदेबाज़ी होती है। जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं और बस मालिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाभ कमा रहे हैं।

जरूरत है सख्त कार्रवाई की

अब वक्त आ गया है कि इस अवैध सवारी व्यवस्था पर रोक लगाई जाए और टूरिस्ट परमिट की गलत उपयोगिता पर सख्त कार्रवाई हो। वरना आने वाले समय में यह एक बड़ा हादसा या घोटाले का कारण बन सकता है।

न्यूज इन शॉर्ट

इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन

शहडोल। इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन संभागीय मुख्यालय शहडोल के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल में किया गया। इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक श्रीमती मनीषा सिंह ने फीता काटकर किया तथा विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इंस्पायर अवार्ड मानक विज्ञान प्रदर्शनी में शहडोल ,उमरिया, अनूपपुर एवं डिंडोरी जिले के नामांकित 127 में से 90 छात्र-छात्राओ ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर दिल्ली से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से विवेक त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी फूलसिंह मरपाची, पं. शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के डॉ. प्रमोद पांडेय, डॉ एम के भटनागर, डाईट प्राचार्य श्रीमती अभिलाषा मिश्रा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय, शिक्षा विभाग के अरविंद पाण्डेय सहित विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित थें।

अब 15 जुलाई तक चलाया जाएगा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान

शहडोल। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिंहा ने जानकारी दी है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अब 15 जुलाई 2025 तक चलाया जाएगा। जिसमें आधार अपडेशन, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, पी.एम. किसान सम्मान निधि पंजीयन, राशनपर्ची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, समग्र ई-केवासी, सामाजिक सुरक्षा पेशन, सिकल सेल एनिमिया स्क्रीनिंग, क्षय रोग स्क्रीनिंग, मातृ वंदना योजना,पी.एम. आवास, इत्यादि के लाभ से छूटे हितग्राहियों को लाभांवित किया जाना है।

राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ शासकीय कार्य

शहडोल। कलेक्ट्रेट कार्यालय शहडोल में जुलाई माह के प्रथम दिवस पर राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ शासकीय कार्य प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ज्योति परस्ते सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहें।

लोगों को मिलेगी डायलिसिस की सुविधा, विधायक ने फीता काटकर किया शुभारंभ

शहडोल। राज्य सरकार द्वारा मरीजो के उपचार के लिए लगातार कार्य कर रही है। किडनी के मरीजो को दूसरे शहरो में दौड़ लगाने से मुक्ति मिलेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपुरी में डायलिसिस मशीन के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक जयसिंह मरावी ने यह बात कही।
विधायक जयसिंह मरावी ने फीता काटकर डायलिसिस की सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रविंदर कौर छाबडा, पूर्व अध्यक्ष महिला वित्त विकास निगम श्रीमती अमिता चपरा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती पूजा बुनकर, पार्षद, चिकित्सक तथा गणमान्य नागरिक एवं मरीजो के परिजन उपस्थित रहें।

जिले में 30 जून को 0.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

शहडोल। अधीक्षक भू-अभिलेख शहडोल ने जानकारी दी है की जिले में 30 जून को जिले में कुल 0.5 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षामापी केन्द्र सोहागपुर में 0 मिमी., बुढ़ार में 0 मिमी., गोहपारू में 0 मि.मी., जैतपुर में 0 मिमी, चन्नौड़ी में 0 मिमी., ब्यौहारी में 0.0 मिमी, दर्ज की गई।

जलगंगा संवर्धन अभियान की पोल खुली- करोड़ों की योजना अधूरी, बारिश शुरू होने के बाद भी जल संरचनाएं अधर में

72 करोड़ खर्च के बावजूद 80प्रतिशत कार्य अधूरा, प्रशासनिक उदासीनता बनी बाधा

विजय मत, शहडोल।
जिले में जल संरक्षण के लिए शुरू किए गए बहुप्रचारित ÷जलगंगा संवर्धन अभियान÷ की सच्चाई समयावधि पूरी होते ही उजागर हो गई है, 30 मार्च से 30 जून तक चले इस अभियान में निर्धारित लक्षणों की पूर्ति नहीं हो पाई। तीन माह तक चले इस अभियान का सोमवार को समापन हुआ, लेकिन ज़मीनी हालात बताने को काफी हैं कि यह अभियान सिर्फ कागजों में सफल रहा, धरातल पर नहीं। करोड़ों रुपये की लागत से बन रही जल संरचनाएं अब भी अधूरी हैं और बारिश की शुरुआत हो जाने के बावजूद जल संग्रहण की पूरी व्यवस्था लटकी हुई है।

खेत तालाब निर्माण में भारी लापरवाही – जिले में 3133 खेत तालाब स्वीकृत किए गए, जिन पर लगभग 72 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 525 तालाब ही अब तक बन पाए हैं, जबकि शेष 2608 तालाबों में कार्य अधूरा है। यह तब है जब 29467 मजदूर इन कार्यों में लगे हुए हैं। सवाल यह उठता है कि मजदूरी और सामग्री पर हो रहा भारी भरकम खर्च आखिर कहां जा रहा है?

पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार भी अधूरा – जिले में पहले से मौजूद 618 तालाबों को रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 346 तालाब ही रिचार्ज हो सके हैं। शेष 272 में काम अब भी चल रहा है, जबकि मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में अधूरे कार्यों से यह साफ है कि वर्षा जल का संरक्षण इस बार भी केवल योजनाओं तक ही सीमित रह जाएगा।

अमृत सरोवरों का भी बुरा हाल –जिले में स्वीकृत 20 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य भी कछुआ गति से चल रहा है। इनमें से एक भी सरोवर समय पर पूरा नहीं हो पाया है, जिससे जल संग्रहण की एक और बड़ी संभावना ध्वस्त हो गई है।

कागजों में बने जलदूत, धरातल पर निष्क्रिय –योजना के तहत 2500 जलदूत तैयार करने का लक्ष्य था, जिसके स्थान पर 3000 जलदूत बनाए तो जरूर गए, लेकिन इनमें से अधिकांश का काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। प्रशिक्षण के नाम पर औपचारिकताएं निभाई गईं, लेकिन इन जलदूतों की वास्तविक भागीदारी कहीं नज़र नहीं आती।

प्रशासनिक लापरवाही से योजनाओं पर पानी फिरा –पूरे अभियान में जिला प्रशासन, जन अभियान परिषद और समाजसेवियों को जोड़ने की

कमिश्नर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई

विजय मत, शहडोल।
कमिश्नर कार्यालय शहडोल के अमरकंटक सभाकक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई कार्यक्रम में उपायुक्त राजस्व श्रीमती मिनिषा पाण्डेय ने शहडोल संभाग के दूर-दराज से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी और समस्याओं तथा शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जन सुनवाई में शहडोल जिले के बाणगंगा रोड़ शहडोल निवासी सेवा निवृत्त शिक्षक अशोक कुमार द्विवेदी ने अर्जित अवकाश नगदीकरण भुगतान करवाने, जिला अनूपपुर ग्राम खमरौंध निवासी लालमन सिंह ने समग्र आईडी अलग करवाने, शहडोल जिले के जयसिंहनगर वार्ड नम्बर 1 निवासी पंकज कुमार गुप्ता ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर के कार्यालय हेतु क्रय की गई सामग्रियो का भुगतान करवाने, शहडोल जिले के ग्राम रतहर निवासी मयाराम यादव ने विद्युत कनेक्शन करवाने हेतु आवेदन उपायुक्त राजस्व श्रीमती मिनिषा पाण्डेय को दिए। उपायुक्त राजस्व ने प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियो को आवेदन प्रेषित कर शीघ्रता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अन्य आवेदको ने भी अपनी शिकायतें एवं समस्याओं संबंधी आवेदन उपायुक्त राजस्व को दिए।

अवैध रूप से तालाब एवं नजूल की भूमि से अतिक्रमण हटाने की शिकायत

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई

विजय मत, शहडोल।
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सोन सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में शहडोल जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं व शिकायतें सुनी तथा निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में शहडोल जिले के ग्राम सपटा निवासी धीरेंद्र सिंह षिक्षक ने सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाष दर्ज करवाने, सोहागपुर निवासी संदीप शुक्ला अवैध रूप से तालाब एवं नजूल की भूमि से अतिक्रमण हटाने, कल्याणपुर निवासी ओमवती आर्मो ने हॉस्टल में कुक पद पर काम दिलाए जाने , ग्राम बैला निवासी कौषल किषोर शुक्ला ने ग्राम पंचायत भादवाही निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच हेतु आवेदन कलेक्टर डॉ केदार सिंह को दिए। जिस पर कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी की ओर आवेदन प्रेषित कर शीघ्रता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में अन्य प्राप्त आवेदनों को कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर प्रेषित कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में अनुविभागीय

शहडोल सांसद को शहडोल की बजाय अंबिकापुर ट्रेन सुविधाओं की फिक्र ज्यादा

शहडोल । जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने अपने बयान मे कहा है कि, शहडोल संसदीय क्षेत्र की माननीय सांसद ने रेल मंत्री से मांग की है कि चेन्नई से बिलासपुर चलने वाली ट्रेन को अंबिकापुर तक चलाया जाए एवं एक ट्रेन अंबिकापुर से अनूपपुर होते हुए मुंबई तक चलाई जाए, इसमे शहडोल का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।
जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने कहा कि शहडोल की जनता द्वारा लगातार शहडोल से मुंबई ट्रेन चलाए जाने की मांग विगत कई वर्षो से की जा रही है,लेकिन शहडोल सांसद को शहडोल की बजाय अंबिकापुर की फिक्र ज्यादा है जो की छत्तीसगढ़ मे आता है। श्री गुप्ता ने कहा शहडोल मे अंबिकापुर की अपेक्षा सर्व सुविधायुक्त यार्ड है, यहां वाशिंग पिट लाइन बनाना ज्यादा सहज है अंबिकापुर मे 2 से 3 लाइनें हैं और शहडोल से 13 लाइनें हैं।जिलाध्यक्ष ने कहा कि शहडोल संसदीय क्षेत्र की जनता ने श्रीमती हिमाद्री सिंह को वोट देकर शहडोल जिले का विकास करने के लिए चुना था न कि छत्तीसगढ के अंबिकापुर का विकास करने के लिए, इस लिए जिले की जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए, माननीय सांसद को शहडोल से ट्रेन चलाए जाने की मांग करनी चाहिए।

युवक को 10 लाख रुपए कमीशन न देने पर बेरहमी से पीटा

विजय मत, शहडोल।
जिले के बुढ़ार में भूमि की खरीदी बिक्री के मामले में एक युवक को 10 लाख रुपए का कमीशन न देने की वजह से जघन्य तरीके से पीटने का मामला सामने आया है। युवक की गंभीर हालत के मद्देनजर उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी चिकित्सा चल रही है।

पुलिस के अनुसार, घटना तीन दिन पहले की है जब लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा नामक युवक के पास प्रकाश पाठक और लच्छू लोधी, दोनों निवासी बुढ़ार, अपनी कार से पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मीकांत पर 10 लाख रुपए का कमीशन मांगते हुए गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने लक्ष्मीकांत को अपनी कार में बिठाकर ले जाने के बाद पहले तहसील के पास और फिर रुगंठा तिराहा के पास बेरहमी से पीटा और भाग गए। घटना के समय कुछ राहगीरों ने लक्ष्मीकांत की स्थिति को देखकर उसकी मदद की और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
बुढ़ार पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में प्रकाश पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लच्छू लोधी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस ने कहा, हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

समस्या

प्रतिमा के चारों ओर अवैध रूप से लगे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सब्जी की दुकानों से लोग परेशान

भूसा तिराहा पर स्थित प्रतिमा बदहाल, गंदगी का अंबार

विजय मत, शहडोल।
शहडोल नगर के प्रमुख भूसा तिराहा पर स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासी समाज के प्रेरणास्त्रोत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा आज उपेक्षा और बदइंतजामी का शिकार बन चुकी है।जहां इस ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण बड़ी धूमधाम से किया गया था, वहीं आज यह स्थल गंदगी, अतिक्रमण और अव्यवस्था की चपेट में आ गया है।

गंदगी का अंबार,दुर्गंध से त्रस्त लोग

प्रतिमा के चारों ओर बेतरतीब फेंका गया कचरा और बदबू से वातावरण दूषित हो चुका है। सब्जी विक्रेताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट और स्थानीय दुकानदारों की लापरवाही ने इस पवित्र स्थल को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। नागरिकों का कहना है कि यहां खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है। यह स्थिति न केवल शर्मनाक है, बल्कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे महानायक का अपमान भी है।

अतिक्रमण बना मुख्य समस्या

प्रतिमा के चारों ओर अवैध रूप से लगे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सब्जी की दुकानें और बेतरतीब वाहन खड़े होने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। यह स्थल अब इको-टैक्सी और ठेले वालों का अघोषित अड्डा बन चुका है, जिससे न केवल सौंदर्य बिगड़ गया है बल्कि राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन की अनदेखी ने बढ़ाई चिंता

स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की उदासीनता से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रतिमा के रखरखाव और आसपास की साफ-सफाई के लिए न कोई नियमित योजना है, न ही अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस कार्रवाई। केवल राष्ट्रीय पर्वों या जयंती पर दिखावटी सफाई की जाती है।

स्थायी समाधान की दरकार

अब वक्त आ गया है कि नगर पालिका और जिला प्रशासन इस ऐतिहासिक स्थल की गरिमा बचाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए। प्रतिमा के चारों ओर लोहे की रेलिंग, हरित क्षेत्र का विकास, और नियमित सफाई व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। साथ ही, आम नागरिकों को जागरूक कर इस स्थल को स्वच्छ और सम्मानजनक बनाए रखने की दिशा में प्रयास आवश्यक हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सीता शुक्ला द्वारा पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस प्रा.लि., प्लॉट नं. 18, इंडस्ट्रियल एरिया, रिछाई, जबलपुर म.प्र. से मुद्रित एवं विजय मत भवन, गायत्री मंदिर रोड, वार्ड नं. 13, शहडोल, म.प्र. से प्रकाशित। संपादक- सीता शुक्ला, प्रधान संपादक- विजय शुक्ला
(*समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार)। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र शहडोल होगा। आर.एन.आई.-पंजीयन नंबर MPHIN/2018/76119, e-mail: vijaymat.sdl@gmail.com